लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 12 मार्च, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 200

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

"शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे दिल जोड़ भी सकते हैं और एक पल में तोड़ भी सकते हैं।"

TODAY WEATHER

DAY 34° Hi

NIGHT 21° Low

संक्षेप

ऑनलाइन गेमिंग की लत पड़ी महंगी, बेटे ने पिता को मुआवजे में मिले 1.77 करोड़ रुपए गंवाए; फिर निगला जहर

नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग और जल्दी मुनाफा कमाने के लालच में एक युवक द्वारा बड़ी रकम गंवाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के 18 वर्षीय युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसकर अपने किसान पिता के 1.77 करोड़ रुपये ठगों को ट्रांसफर कर दिए। शिकायत के आधार पर देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में अभिमन्यु ने बताया कि जनवरी 2025 में उसने प्ले स्टोर से स्पोर्ट्स बाजी, प्रोबो और ड्रीम11 जैसी गेमिंग ऐप डाउनलोड कर उनमें पैसे लगाना शुरू किया। जून 2025 में इन ऐप्स के बंद होने के बाद उसे यूट्यूब पर विन अड्डा नाम की एक गेमिंग वेबसाइट का विज्ञापन दिखाई दिया। वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद उसके व्हाट्सऐप पर विदेशी कोड (+237, +234, +94 आदि) वाले अनजान नंबरों से कई तथाकथित वीआईपी लिंक आने लगे। ठगों ने उसे कम पैसे लगाकर दोगुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया। शुरुआत में मामूली लाभ देकर उसका भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद युवक ने अपने और अपने पिता के पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के कुल पांच खातों से यूपीआई के जरिए रकम ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच उसने करीब 1.77 करोड़ रुपये ठगों के खातों में भेज दिए। जब युवक ने अपनी मूल रकम और मुनाफा वापस मांगा तो जालसाजों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और उल्टे और पैसे जमा कराने का दबाव बनाने लगे।

एलपीजी की किल्लत पर भड़के संजय राउत, पीएम मोदी को याद दिलाया 'नाले से गैस' वाला बयान

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार के आश्वासन झूठे साबित हुए हैं। राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने एलपीजी और ईंधन की कमी के कारण रेस्तरां और अन्य उद्योगों के कथित तौर पर बंद होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष से उत्पन्न स्थिति है। व्यावसायिक और घरेलू गैस की कमी है। जब संघर्ष शुरू हुआ, तब मोदी सरकार ने कहा था कि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के आश्वासन विफल रहे हैं। मुंबई और अन्य शहरों में रेस्तरां बंद हो रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि वाहन क्षेत्र में भी खतरा मंडरा रहा है। मोरबी में टाइल उत्पादन बंद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहे हैं। पीएम मोदी एक वैज्ञानिक हैं, और कुछ साल पहले उन्होंने नाले से गैस बनाने का प्रयोग किया था। उन्हें मुंबई में भी ऐसा ही एक संयंत्र शुरू करना चाहिए।

एर्नाकुलम में पीएम मोदी बोले-

'युवाओं की क्षमता पर कांग्रेस को भरोसा नहीं', राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वे कुल 16,450 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। केरल के एर्नाकुलम में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राजकुमार को यह भी नहीं पता कि भारत के युवा ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में चमत्कार कर रहे हैं।

इसके बाद, प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। यहां मुख्य रूप से गैस पाइपलाइन नेटवर्क पर जोर दिया गया है, जिससे नीलगिरी और इरोड जिलों के करीब 8.8 लाख घरों तक रसोई गैस पहुंचेगी और 200 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी तमिलनाडु में 89 ग्रामीण सड़कों और चेन्नई में एक बड़े ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, तमिलनाडु को पड़ोसी राज्यों और पूर्वी भारत से जोड़ने के लिए दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य दक्षिण भारत में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों में, LDF और UDF ने युवा शक्ति के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस को तो युवाओं की क्षमता पर भरोसा तक नहीं है। कांग्रेस के राजकुमार को यह भी नहीं पता कि भारत के युवा ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में चमत्कार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं है कि भारत में कई कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि केरलम के युवा ड्रोन स्टार्टअप्स खड़ा कर रहे हैं। वह एक छोटे से दायरे तक सीमित हैं और भारत की प्रगति को नहीं देख पा रहे हैं।

UDF-LDF केरल के विकास में बाधा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, UDF और LDF के बारी-बारी से सत्ता में आने के ढर्रे ने केरल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वे सोचते हैं कि 5 या 10 साल बाद वे फिर से सत्ता में लौट आएंगे, इसलिए वे केरल के विकास के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। केरल में भ्रष्टाचार का यह एक बड़ा कारण है। यही वजह है कि यहां विकास परियोजनाएं रुक जाती हैं।

'केरलम' और मलयाली संस्कृति का सम्मान

प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे गर्व है कि भारत और पूरी दुनिया अब इस महान राज्य को केरलम पुकार रही है। मुझे गर्व है कि यह कार्य भाजपा-एनडीए सरकार द्वारा किया गया है। यह आपकी भावनाओं और मलयालम संस्कृति की समृद्ध महानता के प्रति हमारा सम्मान है।

'हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही वहां की सरकारें'

पीए मोदी ने कहा, मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही हैं। मैं उन सभी सरकारों का आभारी हूं। वहां हर देश में जो हमारी एंबेसीज़ हैं, हमारे मिशन हैं, वे 24×7 उनकी मदद कर रहे हैं।

इतने बड़े वैश्विक संकट में राजनीति ढूंढ रही कांग्रेस: पीएम मोदी

मध्य पूर्व में जारी तनाव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं और हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं। फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने की रील बनाने का अभियान शुरू कर सकें। यही उनका खेल है।

खाड़ी संकट और भारतीयों की सुरक्षा पर बोले पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा, खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आपकी चिंताएं स्वाभाविक हैं। हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सत्ता में भाजपा-एनडीए सरकार है। जब भी हमारे नागरिक किसी दूसरे देश में फंसते हैं, हम उनकी मदद के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। चाहे इराक में नर्सों को बचाना हो या यमन में आतंकवादियों से फादर टॉम को छुड़ाना हो, आज का भारत संकट के समय में अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। आज भी हमारा प्रयास यही है कि इस संघर्ष में फंसे भारतीयों को सुरक्षा और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक बन गया है। हमारा प्रयास है कि केरल भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ, वेस्ट कल्लाडा में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना की आधारशिला रखी गई है।

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

संसद में रविशंकर प्रसाद और राहुल गांधी आमने-सामने

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है। विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस दौरान पीएम मोदी पर राहुल गांधी और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बीच हॉट टॉक देखने को मिली। बता दें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 9 घंटे का समय दिया है। सदन में दोपहर बाद गृहमंत्री अमित शाह विपक्ष के स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक बार फिर एपस्टीन फाइल, भारत-अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा उठाया।

नेता प्रतिपक्ष को बोला नहीं दिया जा रहा: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया गया। उन्होंने कहा, जब मैंने सदन में पीएम के कॉम्प्रोमाइज होने के मुद्दे उठाया, तो रोक दिया गया। लोकसभा में बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'यहां चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका के बारे में है। कई बार मेरा नाम लिया गया है और मेरे बारे में अजीब बातें कही गई हैं। यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हर बार जब हम बोलने के लिए उठते हैं, तो हमें बोलने से रोक दिया जाता है। पिछली बार जब मैंने बात की थी, तो मैंने हमारे PM द्वारा किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था।'

सपा सांसद ने सदन में पढ़ी शायरी, लगे ठहाके

समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक शायरी की। उसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको इजहार की जरूरत है।

सपा ने लोकसभा स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया अयोध्या सांसद का नाम

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया।

राघव चड्ढा ने सदन में उठाया प्रीपेड रिचार्ज का मुद्दा

आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, 'आज मैंने सदन में प्रीपेड रिचार्ज कराकर अपना फोन चलाने वाले उपभोक्ताओं का मुद्दा उठाया। जब रिचार्ज की वैद्यता समाप्त हो जाती है तब आउटगोइंग कॉल का बंद होना समझ आता है लेकिन इनकमिंग कॉल भी उसके साथ बंद कर देना उचित नहीं है। ये टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है जिस पर रोक लगनी चाहिए... मैंने मांग रखी कि कम से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल चालू रहनी चाहिए ताकि देश का आम आदमी राइट टू कम्युनिकेशन सरेंडर ना करें...'

लोकसभा में जोरदार बहस, रविशंकर प्रसाद से बोले राहुल गांधी, मेरे बारे में अजीब बातें कही गईं

लोकसभा में बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'यहां चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका के बारे में है। कई बार मेरा नाम लिया गया है और मेरे बारे में अजीब बातें कही गई हैं। यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हर बार जब हम बोलने के लिए उठते हैं, तो हमें बोलने से रोक दिया जाता है। पिछली बार जब मैंने बात की थी, तो मैंने हमारे PM द्वारा किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था...'

देश के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, डार्विन लैब्स के को-फाउंडर आयुष वर्शनेय अरेस्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटालों में गिने जा रहे करीब ₹20,000 करोड़ के कथित बिटकॉइन स्कैम में CBI ने पहली गिरफ्तारी की है। इस मामले में Darwin Labs के को-फाउंडर आयुष वर्शनेय को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी श्रीलंका के कोलंबो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर के आधार पर उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मामला 2015 में शुरू हुई GainBitcoin स्कीम से जुड़ा है। इस स्कीम की शुरुआत अमित भारद्वाज (अब मृत), उनके भाई अजय भारद्वाज और उनके सहयोगियों ने की थी। योजना के तहत निवेशकों को हर महीने 10 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच दिया जाता था और दावा किया जाता था कि यह मुनाफा बिटकॉइन माइनिंग के जरिए कमाया जा रहा है। निवेशकों को क्रिप्टो एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीदकर कंपनी के प्लेटफॉर्म पर क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करने के लिए कहा जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि पूरी स्कीम मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल पर चल रही थी। इसमें पुराने निवेशकों को नए लोगों को जोड़ने पर अतिरिक्त लाभ देने का वादा किया जाता था। इसी वजह से यह स्कीम तेजी से देश के कई हिस्सों में फैल गई और काफी लोगों ने इसमें पैसा लगाया। शुरुआत में कुछ समय तक निवेशकों को बिटकॉइन में भुगतान किया गया लेकिन 2017 के बाद भुगतान कम होने लगा। बाद में कंपनी ने अचानक MCAP नाम की अपनी कथित क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान करना शुरू कर दिया, जिसकी कीमत बिटकॉइन के मुकाबले काफी कम थी।

देशभर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और पूरी स्कीम पोंजी स्कीम की तरह संचालित हो रही थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच के दौरान देशभर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली-एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, नांदेड़, कोल्हापुर और बेंगलुरु समेत कई शहरों में कार्रवाई की गई। अलग-अलग राज्यों में दर्ज कई मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इन सभी मामलों की जांच CBI को सौंप दी थी। इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कर रही है। ईडी अब तक भारत और विदेशों में कई संपत्तियां अटैच कर चुका है।

एडवेंचर टूरिज्म का नया हब बनेगा यूपी, पर्यटन नीति के तहत निवेशकों को बड़ा न्योता

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को रोमांचक और अनुभव आधारित पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गर्मियों के मौसम में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत एडवेंचर टूरिज्म परियोजनाओं में निवेश के लिए उद्यमियों, संस्थाओं और निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है।

सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश के प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म गंतव्यों में शामिल करना है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य में पर्यटन को केवल दर्शनीय स्थलों तक सीमित न रखकर उसे रोमांचक अनुभवों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की

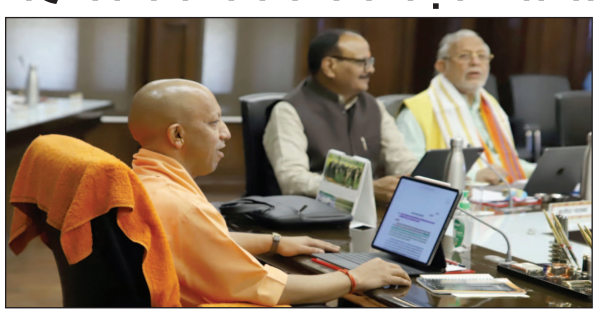

भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता एडवेंचर टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है और निजी क्षेत्र की भागीदारी से इसे नई पहचान दी जाएगी। पर्यटकों की बदलती रुचियों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों को तीन प्रमुख श्रेणियों—भूमि आधारित, जल आधारित और वायु आधारित—में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके माध्यम से युवाओं और रोमांच प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य को भी नई दिशा देने का लक्ष्य है। भूमि आधारित एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत एटीवी (ऑल-टेरेन व्हीकल) टूर, बंजी जंपिंग, साइकिलिंग टूर, जीप सफारी और मोटरसाइकिल टूर जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन गतिविधियों के जरिए रोमांच पसंद पर्यटकों को नया अनुभव देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

जल आधारित एडवेंचर टूरिज्म के तहत कयाकिंग, राफ्टिंग, रिवर क्रूजिंग और आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर विकसित करने की योजना है, जिससे नदियों और जलाशयों से जुड़े क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ सकेंगी। वहीं वायु आधारित एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत हॉट एयर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के तहत निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी (अधिकतम दो करोड़) का प्रावधान है।

ऐतिहासिक फैसला! | देश का ऐसा पहला मामला

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए 'पैसिव यूथेनेशिया' की अनुमति दी

नई दिल्ली, एजेंसी। एक अहम डेवलपमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहली बार 2018 के कॉमन कॉज जजमेंट में तय लीगल फ्रेमवर्क के तहत पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दी, जिसे 2023 में अपडेट किया गया। यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिया, जिसने भारत में सम्मान के साथ मरने के अधिकार के बदलते कानून में एक अहम मोड़ ला दिया। यह ऑर्डर 32 साल के हरीश राणा के पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जो एक बिल्डिंग से बुरी तरह गिरने के बाद 13 साल से इर्रिवर्सिबल वेजिटेटिव स्टेट में हैं।

आज का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला होगा क्योंकि यह पैसिव यूथेनेशिया पर 2018 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आगे बढ़ाता है। आज का हरीश राणा का फैसला उन पहलुओं को साफ़ करता है कि पैसिव यूथेनेशिया को उन मामलों में कैसे लागू किया जाना चाहिए जहाँ मरीज़ की जान फीडिंग ट्यूब से चल रही हो – कुछ ऐसा जो पिछले फैसले में साफ़ तौर पर बताया नहीं गया था।

हरीश राणा का केस इस मायने में अनोखा है कि मेडिकल राय में यह माना गया था कि उनकी हालत ठीक नहीं हो सकती, लेकिन यह बात कि उनकी ज़िंदगी मेडिकल ट्यूब से दिए जा रहे खाने से चल रही थी, 2018 की गाइडलाइंस में शामिल नहीं थी। और इसलिए, 2018 की गाइडलाइंस के तहत दिया गया तरीका – वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट को हटाना – हरीश राणा के लिए हॉस्पिटल लेवल पर पैसिव यूथेनेशिया करने में रुकावट पैदा कर रहा था।

इसी वजह से हरीश राणा के माता-पिता को कोर्ट जाना पड़ा। उनकी अर्जी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसने आज अपने आदेश में हरीश राणा का हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट हटाने की इजाज़त दे दी, जिससे 32 साल के इस शख्स को इज्जत से मरने का मौका मिला।

15 दिन तक लगता है भव्य मेला, भक्तों की हर मुराद पूरी करती है मां बाला सुंदरी

नई दिल्ली, एजेंसी। 19 मार्च से देशभर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में हर देवी मंदिर में खास तैयारी होने लगती है। देश के कई ऐसे मंदिर हैं, जहां चैत्र नवरात्रि के आगमन के साथ ही मेले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर में महामाया का देवी मां बाला सुंदरी मंदिर स्थित है, जहां 15 दिनों तक मेले का आयोजन चलता है।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर में महामाया की देवी मां बाला सुंदरी का मंदिर है, जहां दर्शन मात्र से ही भक्तों के पाप कट जाते हैं। मां बाला सुंदरी जी को शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और पारिवारिक जीवन में शांति और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। लोगों का मानना है कि कोई भी सच्चा भक्त अपने मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटता।

मंदिर के गर्भगृह में मां की अष्टभुजी प्रतिमा और पिंडी विराजमान हैं, जो अस्त्र और शस्त्र के साथ भक्तों को बाल्यावस्था रूप में दर्शन देती हैं। माना जाता है कि मां की पिंडी स्वयंभू है जो कि भक्त लाला रामदास को नमक की बोरी में मिली थी, और उन्होंने स्वप्न में आकर भक्त को मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। मान्यता के अनुसार, 1573 ईस्वी में लाला रामदास नामक एक स्थानीय दुकानदार को देवी मां की पिंडी स्वरूप में दर्शन दिए थे। दुकानदार नमक की बोरी को यूपी के सहारनपुर से लेकर आया था और त्रिलोकपुर में आकर मां का मंदिर बनवाया था।

स्थानीय मान्यता के मुताबिक लाला रामदास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मंदिर का निर्माण कर सकें। ऐसे में उन्होंने सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश की मदद ली, जिसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण हो सका। इसके बाद मंदिर को रखरखाव और जीर्णोद्धार का काम राजा फतेह प्रकाश और राजा रघुबीर प्रकाश ने कराया था। देवी मां बाला सुंदरी को राजपूतों की कुलदेवी भी माना जाता है, जो हमेशा विजय का वरदान देती हैं।

चैत्र नवरात्रि में भक्त भारी संख्या में मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहां 15 दिन तक लगने वाला मेला भी भक्तों के आकर्षण का बड़ा केंद्र होता है। नौ दिन तक मां के अद्भुत श्रृंगार के साथ दर्शन होते हैं।

कोर्ट ने शाही इमाम पर ठोका 6.94 करोड़ का जुर्माना, मस्जिद-दरगाह और मकान पर चल सकता है बुलडोजर

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमामपर गंभीर आरोप लगे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप में कोर्ट ने ईमाम और उनके भाई पर 6.194 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशासन के मुताबिक, गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाए जाने का आरोप है। इस मामले में तहसीलदार न्यायालय ने कब्जाधारियों को जमीन खाली करने का आदेश दिया है और भारी जुर्माना भी लगाया है।

प्रशासन का दावा है कि गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की है। राजस्व रिकॉर्ड में इसे पौधारोपण के लिए आरक्षित बताया गया है। स्थानीय लेखपाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1340 वर्ग मीटर जमीन पर संभल की ऐतिहासिक जमा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी और उनके भाई मेहताब हुसैन का मकान, मस्जिद और दरगाह बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह निर्माण कई दशक पहले किया गया था। इस जमीन पर शाही ईमाम और उनके भाई का पूरी तरह से कब्जा है।

जमीन खाली करने का दिया निर्देश

मामले की जांच के बाद तहसीलदार की कोर्ट ने ईमाम और उनके भाई को जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों पर करीब 6.194 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन के अनुसार, आदेश के बाद संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में जमीन खाली नहीं की जाती है तो राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन कब्जा हटाने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा। यानी मस्जिद, मकान और दरगाह को बुलडोजर चलेगा। प्रशासन के इस आदेश के बाद से गांव सैफ खां सराय में हडकंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईमाम और उनके भाई का परिवार यहां रहता है।

कोर्ट ने ईमाम का सुना पक्ष

वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी ने इस जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। इमाम पक्ष की ओर से कहा गया कि यह स्थान एक धार्मिक स्थल है और मस्जिद व मजार का निर्माण कई वर्ष पहले हुआ था। उनका कहना है कि यह परिसर वक्फ बोर्ड में दर्ज है और यहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रम प्रशासन की जानकारी में आयोजित होते रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग का कहना है कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जमीन ग्राम समाज की है और उस पर किए गए निर्माण को वैध नहीं माना जा सकता। यह मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर प्रशासन की सख्ती भी चर्चा का विषय बन गई है।

17 मस्जिदें, 12 मजारें और दो मदरसों पर चला बुलडोजर

संभल जिले में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पहले भी कई स्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सलेमपुर सालार, राया बुजुर्ग और नरौली जैसे क्षेत्रों में अवैध निर्माण हटाए गए हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में लगभग 17 मस्जिदें, 12 मजारें और दो मदरसों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

परिषदीय विद्यालय की बाउंड्रीवाल निर्माण में मजदूर बना मासूम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में इंसानियत और कानून को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के काशीराम का पुरवा, मौजा डोभियारा स्थित एक विद्यालय में बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान मासूम बच्चों से ईंट और मसाला ढुलवाने का काम कराया गया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि समाचार पत्र नही करता है वीडियो में एक जिम्मेदार का बयान न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि बाल अधिकारों और कानून की खुली अवहेलना भी माना जा रहा है। जिन नन्हें हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, जिम्मे दारो द्वारा नाबालिग बच्चो से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों में इस मामले को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि विद्यालय परिसर में बच्चों से मजदूरी कराना बाल श्रम कानून का सीधा उल्लंघन है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले में शिक्षा विभाग और प्रशासन की भूमिका पर भी निगाहें टिकी हैं। लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित शिक्षक और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह घटना न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे को भी उजागर करती है। इस बावत बल्दीराय के खन्ड शिक्षा अधिकारी श्याम विहारी ने बताया कि इसकी जानकारी है।

इश्क में आईमन अहमद ने तोड़ी मजहब की दीवार, कृतिका बन हिंदू प्रेमी शिवम के साथ मंदिर में लिए सात फेरे

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। रायबरेली के लालगंज में प्रेम विवाह का एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी हिंदू युवक से शादी कर ली। विवाह हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में संपन्न हुआ। शादी के बाद युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम भी बदल लिया।

मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव का है। गांव निवासी आईमन अहमद का गांव के ही युवक शिवम के साथ करीब पांच वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को विवाह का रूप देने का निर्णय लिया। परिवार और समाज की आशंकाओं के बीच दोनों ने शादी करने का फैसला किया।

दोनों ने ऐहार स्थित बाल्हेश्वर मंदिर में विधि-विधान से हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह कर लिया। पुरोहित की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लिए। अग्नि को साक्षी मानकर जीवनभर साथ निभाने की शपथ ली। विवाह के बाद आईमन ने हिंदू धर्म अपनाकर नया नाम कृतिका रख लिया। शादी के बाद नवविवाहित दंपती शिवम और कृतिका ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता आपसी विश्वास और प्रेम पर आधारित है। दोनों ने साथ मिलकर जीवन बिताने का निर्णय लिया है।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं ! गाजीपुर में 15 साल के लड़के की पीट–पीटकर हत्या, गुस्से में गांववालों ने हाईवे किया जाम

आर्यावर्त संवाददाता

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बड़े भाई की शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और हल्दी की रस्म का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इसी दौरान 15 वर्षीय किशोर की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिवार और गांव में भारी आक्रोश फैल गया।

यह मामला गाजीपुर जिले के जंगीपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा उधउपुर गांव का है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय सुधरन राजभर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सोमवार की देर शाम उसके घर में बड़े भाई की शादी को लेकर हल्दी की रस्म चल रही थी। परिवार और रिश्तेदार इस खुशी के मौके पर जुटे हुए थे। इसी बीच गांव से कुछ दूरी पर

रहने वाले दो युवकों ने सुधरन को फोन कर बुलाया।

युवकों ने उसे लाठी से पीट-पीटकर मार डाला

बताया जा रहा है कि फोन आने के बाद सुधरन घर से निकलकर उनसे मिलने चला गया। इसके बाद आरोप है कि दोनों युवकों ने उसे लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि वह सड़क किनारे लहूलुहान हालत में गिर पड़ा। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे घायल अवस्था में देखा और इस घटना की जानकारी फोन के जरिए उसके परिवार वालों को दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सुधरन खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ है और बेहोश है। इसके बाद परिजन उसे तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मऊ जिले के एक अस्पताल में रेफर कर दिया। अस्पताल में उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई। आखिरकार मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घर में मचा कोहराम

मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन जब शव को लेकर गांव पहुंचे तो पूरे गांव में गुस्सा फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे जाम करने का प्रयास भी किया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जंगीपुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोर को उसके दो परिचित युवकों ने घर से बुलाकर लाठी-डंडों से पीट दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, परिवार की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक बिरनो थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं और मृतक से उनका पहले से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।

पारा बाजार में लगा नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर, 330 मरीजों की हुई जांच

सुल्तानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पारा बाजार में डॉ.अशफ़ाक अहमद खान के आवास परिसर में बुधवार को इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अमेठी की ओर से नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आंखों की जांच कराई और चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया।शिविर में कुल 330 मरीजों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 173 महिलाएं और 157 पुरुष शामिल रहे। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अमेठी से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की आंखों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं व परामर्श दिया। इस दौरान आंखों से संबंधित विभिन्न बीमारियों का परीक्षण और उपचार किया गया। शिविर में डॉ. एस.पी. सिंह, डॉ. सुनीता, डॉ. रेणु, डॉ. संयोगिता, डॉ. ज्योति, डॉ. आभा, कंपाउंडर कल्पनाथ, डॉ. कमर खान और डॉ. अशफ़ाक अहमद सहित अन्य चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की।

14 महीने के बच्चे ने निगल लिया 2.5 इंच का नुकीला स्क्रू, बिना ऑपरेशन डॉक्टरों ने कैसे बचाई जान?

आर्यावर्त संवाददाता

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीक का लोहा मनवाया है। सिद्धार्थनगर के रहने वाले महज 14 महीने के एक बच्चे के पेट से डॉक्टरों ने ढाई इंच लंबा और बेहद नुकीला स्क्रू सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि बिना किसी बड़े ऑपरेशन या पेट में चीरा लगाए, डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी तकनीक के जरिए इस जानलेवा खतरे को शरीर से बाहर निकाला।

जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले पशुपतिनाथ दुबे का 14 माह का बेटा गर्वित 4 दिन पहले अपने घर में खेल रहा था। खेलते समय उसने पास पड़ा ढाई इंच का एक लोहे का स्क्रू निगल लिया। परिवार को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि बच्चे ने इतना बड़ा और खतरनाक कुछ निगल लिया है।

जब बच्चे के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ, तो परिजनों ने इसे सामान्य समस्या समझा और कस्बे के ही एक मेडिकल स्टोर से दवा लाकर उसे खिला दी। दवा खाने के बाद बच्चा थोड़ी देर शांत रहता, लेकिन फिर दर्द से तड़पने और चिल्लाने लगता। जब हालत में सुधार नहीं हुआ, तो परिजन उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां से उसे तुरंत गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

एक्स-रे में दिखा मौत का कांटा

परिजनों ने बच्चे को गोरखपुर के चरगांवा स्थित सिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में देर रात भर्ती कराया। यहां डॉ। विवेक मिश्रा और उनकी टीम ने तत्काल बच्चे का परीक्षण किया और एक्स-रे कराया। एक्स-रे की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर और परिजन दोनों दंग रह गए। बच्चे के पेट के भीतर ढाई इंच का एक बड़ा और नुकीला स्क्रू फंसा हुआ था, जो धीरे-धीरे आंतों की ओर बढ़ रहा था।

3 दिन तक चली कड़ी निगरानी और जटिल प्रक्रिया

बच्चे की उम्र बहुत कम थी, इसलिए बड़ा ऑपरेशन करना जोखिम भरा हो सकता था। डॉक्टरों ने उसे पीडियाट्रिक यूनिट में भर्ती किया और हर चार घंटे में सीरियल एक्स-रे के माध्यम से स्क्रू की स्थिति पर नजर रखी। कुछ समय बाद स्क्रू टर्मिनल हीलियम (छोटी और बड़ी आंत का जोड़) के पास जाकर रुक गया। डॉक्टरों ने बच्चे को बड़े ऑपरेशन के दर्द से बचाने के लिए कोलोनोस्कोपी करने का साहसिक निर्णय लिया। प्रक्रिया के दौरान एंडोस्कोप को आंतों के भीतर डाला गया। जांच में पाया गया कि स्क्रू मल में फंसा हुआ था। एंडोस्कोपिक उपकरणों की सहायता से बेहद सावधानी पूर्वक उस नुकीले स्क्रू को पकड़कर बाहर खींच लिया गया।

जानलेवा हो सकती है लापरवाही

सफल प्रक्रिया के बाद डॉ। विवेक मिश्रा ने बताया कि बच्चों में फॉरेन बॉडी (बाहरी वस्तु) निगलने के मामले अक्सर आते हैं, लेकिन यह केस बेहद संवेदनशील था। उन्होंने कहा- नुकीले स्क्रू का मामला बहुत जोखिम भरा होता है। यह आंतों में कहीं भी छेद कर सकता था, जिससे शरीर के भीतर संक्रमण फैल जाता और स्थिति जानलेवा हो सकती थी।

डॉक्टर ने सभी अभिभावकों को सलाह दी है कि यदि कोई बच्चा सिक्का, बटन, सेल या स्क्रू जैसी कोई भी वस्तु निगल लेता है, तो मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेने के बजाय तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले जाएं और एक्स-रे जरूर कराएं।

अब पूरी तरह स्वस्थ है गर्वित

3 दिनों तक दर्द से तड़पने के बाद अब नन्हा गर्वित पूरी तरह सुरक्षित और दर्द मुक्त है। बिना टांके और बिना चीरे के हुए इस सफल इलाज से परिजन भी बेहद खुश हैं और उन्होंने डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है।

21 रमजान को मौला अली की शहादत पर निकला जुलूस

सुल्तानपुर। बल्दीराय क्षेत्र के चक्कारीभीट गांव में 21 रमजान के पवित्र अवसर पर हजरत मौला अली (अ.स.) की शहादत की याद में पारंपरिक जुलूस और मजलिस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े गमगीनऔर श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ।

चक्कारीभीट के बड़े इमामबाड़े में सबसे पहले मौला अली (अ.स.) की शहादत पर एक भावपूर्ण मजलिस आयोजित की गई। मजलिस के बाद शबीहे ताबूत (ताबूत) निकाला गया, जो पुराने निर्धारित रास्ते से होते हुए गांव के कर्बला पहुंचा। वहां ताबूत को सिपुर्द-ए-खाक किया गया। जुलूस में शामिल अजादारों ने मौला अली की शहादत पर नौहे पढ़े, मातम किया और सीना-जनी करते हुए 'या अली' के सदाओं के साथ। जुलूस के दौरान मस्जिद में नमाजी मारा गया वावेला नौहा पढ़ा और मातम करते हुए। पूरा जुलूस शोकाकुल माहौल में अदब और सम्मान के साथ संपन्न हुआ।

बरेली में दो नई टाउनशिप का रास्ता साफ, बीडीए को मिले 150 करोड़, 12 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तेजी से बढ़ती आबादी और आवास की जरूरत को देखते हुए एक बड़ी योजना को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) को दो नई टाउनशिप बसाने के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बीडीए इन टाउनशिप के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया तेज करने जा रहा है।

इन टाउनशिप को विकसित करने के लिए आसपास के 12 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे आने वाले समय में शहर में रहने के लिए नए और बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध होंगे। BDA के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से शहर का दायरा बढ़ेगा और लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलोनियां मिलेंगी।

12 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

नई टाउनशिप विकसित करने के लिए बीडीए ने जिन गांवों को चिन्हित किया है, उनमें आसपुर, खूबचंद, अड्पुरा, जागीर, अहिलादपुर, बरकापा, कुम्हरा, कलापुर, मोहरनियां, नवदिया, कुर्मियांन और हरहरपुर शामिल हैं। इन गांवों की जमीन को अधिग्रहित कर योजनाबद्ध तरीके से नई कॉलोनियां बसाई जाएंगी। बीडीए अधिकारियों के अनुसार, जमीन अधिग्रहण से पहले संबंधित गांवों में सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद जमीन की कीमत तय कर किसानों और जमीन मालिकों से बातचीत की जाएगी। पूरी प्रक्रिया सरकार के नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों का कहना है कि इन टाउनशिप में सड़क, पार्क, बिजली, पानी, सीवर, स्कूल और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इससे लोगों को व्यवस्थित और बेहतर माहौल में रहने का मौका मिलेगा।

आठ शहरों को मिला 425 करोड़ का बजट

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आठ शहरों को कुल 425 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इसमें बरेली विकास प्राधिकरण को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। 150 करोड़ रुपये मिलने से बीडीए को जमीन खरीदने और टाउनशिप की योजना को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। सरकार की ओर से दी गई यह राशि प्राधिकरण को अधिकतम 20 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य नई टाउनशिप बसाने के लिए जमीन की व्यवस्था करना और भविष्य में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। इस योजना में आवास विकास परिषद को भी शामिल किया गया है। हालांकि, बरेली को मिला बड़ा बजट इस बात का संकेत है कि शहर का औद्योगिक और आवासीय महत्व लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अब बीडीए जल्द ही चिन्हित गांवों में सर्वे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटेगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। अगर यह योजना तय समय पर पूरी हो जाती है तो बरेली में आवास की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। साथ ही शहर के विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मायावती के वोटबैंक में सेंध की तैयारी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। कांग्रेस ने बसपा के वोटबैंक में सेंध लगाने का प्लान बना लिया है। दरअसल, कांशीराम के जन्मदिन (15मार्च) के सम्मान में यूपी कांग्रेस एक हफ्ते तक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसकी शुरुआत लखनऊ के जुपिटर हाल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से 13 मार्च को होगी। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मुख्य वक्ता के तौर पर हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने कांशीराम के जन्मदिन को सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में दलित-पिछड़े चिंतकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्योता भेजा गया है।

यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल के इस कदम को खासकर दलित वोटबैंक को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, कांग्रेस को लगता है कि कांशीराम की विरासत संभाल रहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अरसे से

बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं और बेहद कम सक्रिय हैं। ऐसे में मान्यवर कांशीराम के बड़े वोटबैंक को अपने पाले में किया जा सकता है।

कांग्रेस की तरफ लौटेंगे कांशीराम के समर्थक!

कांग्रेस का मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को लगातार राहुल लेकर चल रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग भी राहुल ने उठाई, इसलिए कांशीराम समर्थक भी कांग्रेस की तरफ लौटेंगे। इससे पहले राहुल ने इन दोनों मुद्दों के साथ ही बीजेपी पर 400 सीटें आने पर संविधान बदल देने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठाया था, जिसका कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को फायदा मिला था। ऐसे में राहुल ने अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनावी दांव चलने का फैसला किया है।

सपा भी कर चुकी ऐलान

1984 में बसपा बनाने वाले कांशीराम को उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में दलितों और दूसरे पिछड़े समुदायों को एक ताकतवर पॉलिटिकल ग्रुप में इकट्ठा करने का क्रेडिट दिया जाता है। 15 मार्च को उनकी जयंती उनके फॉलोअर्स, खासकर बहुजन समाज पार्टी मनाती है। इस साल, समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वह इस मौके को बड़े पैमाने पर मनाएगी और इस दिन को PDA दिवस के तौर पर मनाएगी। मायावती ने ऐसा करने के लिए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की आलोचना की और इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि SP का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से बहुजन समाज के नेताओं और आइकॉन के प्रति बेइज्जती दिखाता रहा है।

प्रयागराज में दो धार्मिक स्थलों का होगा पर्यटन विकास, 3 .46 करोड़ रुपये खर्च होंगे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने प्रयागराज में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अमल में लाने की तैयारी कर ली है। करछना स्थित फलाहिरी बाबा मंदिर और सोरांव तहसील के दुर्गा मंदिर देवी धाम पचदेवा के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 3.46 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। इससे इन आस्था केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि तीर्थ नगरी प्रयागराज देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग लोकप्रिय तीर्थस्थलों के साथ-साथ कम प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसी क्रम में करछना स्थित फलाहिरी बाबा मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1.64 करोड़ रुपये से अधिक तथा सोरांव तहसील के दुर्गा मंदिर देवी धाम पचदेवा के सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 1.82 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।उन्होंने बताया कि फलाहिरी बाबा मंदिर के विकास के लिए 40 लाख रुपये और सोरांव तहसील स्थित दुर्गा मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 45 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक लाइटिंग, भव्य प्रवेश द्वार, श्रद्धालुओं के लिए यात्री शेड, स्टाम्प फ्लोरिंग युक्त मार्ग, बैठने के लिए बेंच, स्वच्छ शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, डस्टबिन, साइनेज और म्यूरल आर्ट जैसे कार्य कराए जाएंगे।

अब एक घंटे के भीतर ही करानी होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री, यूपी में एक अप्रैल से लागू होगा नया नियम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। अब संपत्तियों की रजिस्ट्री बुक हुए स्लॉट से एक घंटे के भीतर ही करानी होगी। इस अवधि में रजिस्ट्री नहीं होने पर स्लॉट स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसके बाद नया अगर उस दिन में स्लॉट खाली होगा तो मिलेगा वरना दूसरे दिन के लिए आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी।

निबंधन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर स्लॉट संबंधित सूचना भी आ गई है। अभी तक पूरे दिन का स्लॉट मिलता है। हालांकि, यह नियम को लागू किए जाने के पीछे विभागीय अधिकारियों का दावा है कि रजिस्ट्री सुबह 10 बजे से शुरू होती है लेकिन, अधिवक्ता 12 बजे के बाद ही क्रेता-विक्रेता को लेकर आते हैं और दोपहर भीड़ बढ़ जाती है।

भीड़ में दस्तावेजों की जांच करना आसान नहीं होता है, नए नियम से हर दस्तावेज को जांचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उधर, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों में चर्चा चल रही है कि रजिस्ट्री विभाग में सर्वर सही नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वर ठप होने पर कुछ लोगों की रजिस्ट्री अटक सकती है।

मामले में अधिकारियों ने दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं को सूचित किया है कि वे क्रेता-विक्रेता को इस बारे में जागरूक करें। एआईजी स्टांप संजय दुबे ने बताया कि एक अप्रैल से नया नियम प्रभावी हो जाएगी। इसकी सूचना अधिवक्ताओं को भी दी जा रही है।

रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की जगह सीधे होगी रजिस्ट्री, तैयार हो रहा मसौदा

निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसके मुताबिक, कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियों के दस्तावेजों का पंजीकरण प्रतिबंधित किया जा सकेगा। रजिस्ट्री से पहले संपत्ति की सही पहचान की जाएगी। रजिस्ट्री के साथ स्वामित्व, अधिकार और कब्जे से जुड़े आवश्यक दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। यदि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे तो पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्री करने से मना कर सकेगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में मसौदा तैयार हो रहा है। जल्द ही इसे अमल में लाने की तैयारी है।

प्रदेश में नहीं पनपने देंगे अब दूसरा छांगुर, धर्मांतरण के मामलों पर निगाह रखे प्रशासन

लखनऊ। जिले में दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेवर में नजर आए। उन्होंने मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय और पंडित अटल विहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा किया। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही तल्ख शब्दों में कहाकि दूसरा छांगुर किसी कीमत पर न पनपने पाए। इसके लिए कड़ी निगरानी करें और प्रभावी कदम उठाएं। इसी के साथ जोड़ा की कानून से बढ़कर कोई नहीं है, माफियाओं पर नकेल कसे रखें। जिले में हिंदु युवतियों के धर्मांतरण और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गहरी पैठ होने की टीस मुख्यमंत्री की उभरकर सामने आई। उन्होंने साफ कहाकि ऐसी स्थिति पर गहरी नजर रखी जाए। अवैध कार्य पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। जिससे फिर कभी कोई छांगुर सिर न उठा सके। जिले में दुष्कर्म के मामलों के बढ़ने पर कड़ी चेतावनी दी। कहाकि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संगठित प्रयास हों। किसी तरह के असामाजिक तत्वों पर फौरी कार्रवाई हो। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहाकि यह विवाद की जड़ है, इसे अधिकारी गंभीरता से लें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया, बोले की भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो।

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल, जनता बदलाव चाहती है : केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल में मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है और लोग परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं से जनता का शासन और प्रशासन पर से भरोसा कमजोर होता जा रहा है। उनका कहना था कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके

कारण आम नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है और वही यह तय करती है कि राज्य की दिशा और दशा क्या होगी। जनता अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर भविष्य के लिए निर्णय लेती है। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले समय में सुशासन, विकास और पारदर्शिता को प्राथमिकता देगी और उसी के अनुरूप अपना निर्णय भी करेगी।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश के प्रत्येक राज्य में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था स्थापित करना है। उनका कहना था कि जब शासन व्यवस्था पारदर्शी होती है तो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचता है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी लक्ष्य के साथ देशभर में सुशासन और विकास की नीति को आगे बढ़ा रही है।

मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना हसनगंज की मिशन शक्ति एवं पिंक बूथ 60 टीम द्वारा छात्राओं और महिलाओं को साइबर सुरक्षा तथा हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक किया गया। यह जागरूकता कार्यक्रम कैलाश छात्रावास के पास आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की छात्राओं और महिलाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड और फर्जी कॉल जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यक्रम का संचालन महिला कांस्टेबल ज्योति सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान करीब 20 से 30 छात्राओं और महिलाओं को डिजिटल माध्यम से होने वाले अपराधों के प्रति सचेत किया गया तथा उनसे बचाव के व्यावहारिक उपाय बताए गए। साथ ही उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके।मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में लखनऊ कमिश्नरेट के 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर एक निरीक्षक, एक अतिरिक्त निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक और एक महिला उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है, ताकि थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को 1090 महिला पावर लाइन, 112 आपातकालीन सहायता सेवा, 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन और 1098 चाइल्डलाइन जैसे महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी दी गई।

संक्षेप

उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में बसों से नि :शुल्क यात्रा की खबर भ्रामक : परिवहन निगम

लखनऊ। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 के लिए 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के दौरान परिवहन निगम की बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर नि :शुल्क यात्रा किए जाने संबंधी सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है, जिसे परिवहन निगम ने पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया है।प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि निगम मुख्यालय स्तर से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 के अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाकर बसों में नि :शुल्क यात्रा की सुविधा देने के संबंध में किसी प्रकार का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही यह जानकारी पूरी तरह भ्रामक है और इससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।प्रधान प्रबंधक (संचालन) ने समस्त क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर प्रसारित इस भ्रामक सूचना का खंडन करते हुए बस अड्डों पर हेल्प डेस्क के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों में नि :शुल्क यात्रा को लेकर किसी प्रकार का असमंजस न रहे।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी चालकों और परिचालकों को भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए, जिससे मार्ग में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। संपर्क सूत्र के रूप में आशीष सिंह को नामित किया गया है।

बीबीएयू में नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टैन्टिन नोवोसेलोव का विशेष व्याख्यान, युवाओं को दिया लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में बुधवार को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कॉन्स्टैन्टिन सेर्गेयेविच नोवोसेलोव ने विशेष व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा ने की। इस अवसर पर आईआईटी कानपुर के रजत श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन समिति की ओर से मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत के साथ हुई, जबकि मंच संचालन प्रो. शूरा दारापुरी ने किया।कॉन्स्टैन्टिन सेर्गेयेविच नोवोसेलोव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह केंद्रित रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति सकारात्मक भावना के साथ कार्य करता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, परिश्रम और लगातार सीखने की इच्छा ही किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति होती है।उन्होंने कहा कि भौतिकी के क्षेत्र में जहां कई चुनौतियाँ हैं, वहीं असीम संभावनाएँ भी मौजूद हैं। हर नई पीढ़ी अपने अनुभव, शोध और नवाचारों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए नए ज्ञान और खोजों की विरासत छोड़कर जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को जिज्ञासा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नए विचारों और आविष्कारों की दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए।कार्यवाहक कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा ने नोवोसेलोव का विश्वविद्यालय आने और विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका विश्वविद्यालय आगमन पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गौरव, सम्मान और प्रेरणा का विषय है।

कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के लिए क्रायोवैसल खरीद को 9 .34 करोड़ रुपये स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु एवं भैंस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को तरल नत्रजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रायोवैसल के क्रय और स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ 34 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।पशुधन विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण और व्यय अनुमोदित कार्ययोजना तथा योजना के लिए निर्धारित गाइडलाइंस का पूर्ण पालन करते हुए किया जाएगा। साथ ही व्यय विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी मद और प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा पशुधन विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना के विस्तार के लिए यूपीनेडा की बैंकर्स के साथ बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के निदेशक इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना के दायरे को प्रदेश में व्यापक स्तर पर बढ़ाना था।बैठक में निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बैंकर्स से आह्वान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने में बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैंकर्स के सहयोग से प्रदेश में घर-घर सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा सकेगा, जिससे आम नागरिकों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति संभव होगी।उन्होंने बताया कि घरेलू सोलर रूफटॉप स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि पिछले आठ महीनों से प्रदेश लगातार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष दो राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है।बैठक में राज्य स्तरीय बैंक समिति की प्रतिनिधि निधि और संजीव द्विवेदी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा आरईसी के अनिल यादव, बैंक ऑफ इंडिया के संजीव कुमार तथा अन्य बैंकिंग संस्थानों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।बैठक के दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं व किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

लखनऊ में नशे के लिए पैसे न देने पर बेटे ने पिता पर किया हमला, हालत गंभीर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। सरोजनी नगर क्षेत्र के बेहसा गांव में नशे के लिए पैसे न देने पर बेटे द्वारा अपने ही पिता पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में गंभीर रूप से घायल वृद्ध को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी पुत्र घटना के बाद से फरार है।पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 3:20 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सरोजनी नगर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि बेहसा गांव में एक व्यक्ति ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल संतलाल रावत (उम्र लगभग 60 वर्ष) को एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए लोकबंधु अस्पताल भेजा गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि संतलाल रावत का पुत्र नीरज रावत (उम्र लगभग 35 वर्ष) नशे का आदी है। वह अपने पिता से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे देने से मना करने पर उसने बाके (धारदार हथियार) से हमला कर अपने पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया।घटना की सूचना मिलने पर घायल की बेटियां भी अस्पताल पहुंच गई हैं। वहीं आरोपी नीरज रावत घटना के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है।पुलिस के अनुसार मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है।

न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 करने की मांग, श्रम मंत्री अनिल राजभर ने दिया आश्वासन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह शीघ्र ही केंद्रीय श्रम मंत्री से भेंट कर पत्रकारों सहित निजी क्षेत्र के सभी अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (पीएफ) से मिल रही मासिक ₹1000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹5000 किए जाने की मांग को मजबूती से उठाएंगे।यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय श्रम मंत्री को संबोधित संबंधित ज्ञापन श्रम मंत्री अनिल राजभर को सौंपा। यह प्रस्ताव यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अयोध्या में आयोजित प्रादेशिक सम्मेलन में पारित किया गया था, जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई थी।प्रतिनिधिमंडल में

यूनियन के प्रादेशिक महामंत्री देवराज सिंह, लखनऊ इकाई के अध्यक्ष शिवशरण सिंह, अब्दुल हसनैन ताहिर और आशीष कुमार सिंह शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री को बताया कि वर्तमान समय में ₹1000 की न्यूनतम पेंशन से अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का जीवन-यापन करना अत्यंत कठिन हो गया है।यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने बताया कि ₹1000 की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण लगभग डेढ़ दशक पहले किया गया था। वर्तमान महंगाई के दौर में यह राशि अत्यंत कम है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारें महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को हजारों रुपये की पेंशन प्रदान कर रही हैं, जबकि निजी क्षेत्र में जीवन के कई दशक पूर्णकालिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को केवल ₹1000 पेंशन मिलना हास्यास्पद और अन्यायपूर्ण है।श्रम मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह शीघ्र ही केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात कर यूनियन की मांग को उनके समक्ष रखेंगे और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए प्रभावी रूप से प्रयास करेंगे।

अलीगंज में अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर व जोनल कार्यालय का लोकार्पण, नागरिकों को एक ही स्थान पर मिलेंगी नगर निगम की सेवाएं

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ द्वारा नागरिकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलीगंज के सेक्टर-बी में निर्मित अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर एवं जोनल कार्यालय (जोन-3) का बुधवार को लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस आधुनिक भवन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्री एवं सांसद राजनाथ सिंह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से आयोजित किया गया।लोकार्पण समारोह में लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि लखनऊ उत्तरी के विधायक डॉ. नीरज बोरा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद पृथ्वी गुप्ता, नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, चीफ इंजीनियर सिविल महेश वर्मा, जोनल अधिकारी आकाश कुमार, जोनल सेनेटरी ऑफिसर मनोज यादव, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।नगर निगम लखनऊ के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 13.11 करोड़ रुपये की लागत आई है। अलीगंज के सेक्टर-बी में पानी की टंकी के पास स्थित यह भवन लगभग 2184 वर्ग मीटर परिसर में विकसित किया गया है, जबकि भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 1297.50 वर्ग मीटर है। भवन को तीन तल—भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल—में तैयार किया गया है।भवन के भूतल पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से सीनियर सिटीजन कम्युनिटी एंड रिक्रिएशनल सेंटर बनाया गया है। यहां मनोरंजन एवं गतिविधि कक्ष, जिम एवं योग कक्ष, लगभग 800 पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय, वित्तीय एवं कानूनी परामर्श कक्ष तथा कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा महिला, पुरुष और दिव्यांगजनों के लिए पृथक शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, जिससे सभी वर्गों के नागरिकों को सुविधा मिल सके।भवन के प्रथम तल पर जोनल अभियंत्रण कार्यालय स्थापित किया गया है, जहां नागरिकों की सुविधा के लिए 16 पटल काउंटर बनाए गए हैं। इन काउंटरों के माध्यम से गृहकर, अभियंत्रण, जलकल, मार्ग प्रकाश, संपत्ति विभाग, उद्यान विभाग, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, नामांतरण, प्रचार एवं अतिक्रमण से संबंधित सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे नागरिकों को नगर निगम के विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।द्वितीय तल पर जोन-3 का जोनल कार्यालय स्थापित किया गया है, जहां से क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक और प्रबंधन कार्य संचालित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस केंद्र के शुरू होने से अलीगंज सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को नगर निगम की सेवाएं अधिक सुगमता और पारदर्शिता के साथ मिल सकेंगी।इस अवसर पर मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों में आधुनिक और नागरिक केंद्रित सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जोन-3 में बनाया गया यह जोनल कार्यालय अत्याधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से युक्त है, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।

नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

लखनऊ। नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान लोहम कंपनी के सीईओ रजत वर्मा और कंपनी के चीफ ऑफ स्टाफ आयुष सबात भी मौजूद रहे। तीनों अतिथियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध सकारात्मक वातावरण की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव, लोहम के सीईओ रजत वर्मा और चीफ ऑफ स्टाफ आयुष सबात का उत्तर प्रदेश में स्वागत किया।बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश को देश में एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च और इंजीनियरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी क्रम में लोहम कंपनी द्वारा प्रदेश में भारत की पहली "रेयर अर्थ टू मैग्नेट" इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्थापित करने की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

सऊदी अरब की मदद के लिए रणभूमि में उतर सकता है पाकिस्तान, युद्ध का दायरा और फैलेगा!

पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात के बीच पाकिस्तान एक बेहद जटिल सामरिक दुविधा में फंस गया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस्लामाबाद के सामने यह कठिन सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वह अपने पुराने सहयोगी सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सऊदी दौरे ने इस बहस को और तेज कर दिया है।

दरअसल ईरान द्वारा सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाओं के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सामरिक रक्षा समझौते की परीक्षा शुरू हो गयी है। इस समझौते के अनुसार यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी सुरक्षा में सहयोग करेगा। इस संकट के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इस बैठक में ईरानी हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा की गयी। दोनों देशों ने साझा रक्षा समझौते के तहत संभावित कदमों पर विचार किया। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यदि पाकिस्तान सऊदी अरब का सैन्य समर्थन करता है तो वह सीधे ईरान के साथ टकराव की स्थिति में आ सकता है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पहले से ही अस्थिर है और ऐसे में नया संघर्ष उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

मगर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता और तेल आपूर्ति के माध्यम से कई बार पाकिस्तान की मदद की है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा लगती है और इन दोनों देशों के बीच भी सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े कई हित हैं। यही कारण है कि अब तक पाकिस्तान ने इस संघर्ष में सीधे शामिल होने से बचने की कोशिश की है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस्लामाबाद खुलकर सऊदी अरब के पक्ष में उतरता है तो इससे ईरान के साथ संबंध गंभीर रूप से बिगड़ सकते हैं और सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति भी है। देश में सुन्नी और शिया समुदाय दोनों की बड़ी आबादी है। ईरान शिया बहुल देश है जबकि सऊदी अरब सुन्नी नेतृत्व वाला राष्ट्र है। ऐसे में यदि पाकिस्तान किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करता है तो देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका भी रहेगी। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये थे और गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तान स्थित अमेरिकी मिशन पर हमला भी बोल दिया था। इसके बाद हालात काबू करने के लिये सुरक्षा बलों को कार्रवाई करनी पड़ी थी जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आयीं। इस घटना ने इस्लामाबाद की चिंता और बढ़ा दी है। पाकिस्तान की सरकार को आशंका है कि यदि वह खुलकर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के समर्थन में सेना उतारता है तो देश में मौजूद शिया समुदाय भड़क सकता है और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी कारण पाकिस्तान की सरकार और सेना अब तक संतुलित नीति अपनाने की कोशिश करती रही है। इसके अलावा, पाकिस्तान की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक परमाणु शक्ति है और मुस्लिम देशों में उसकी सेना को काफी प्रभावशाली माना जाता है। यदि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ सैन्य रूप से जुड़ता है तो इससे पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसके अलावा यह संघर्ष वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का कोई भी फैसला केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान फिलहाल सीधे युद्ध में शामिल होने से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि सऊदी अरब पर हमले बढ़ते हैं और रक्षा समझौते के तहत दबाव बढ़ता है तो इस्लामाबाद के सामने कठिन निर्णय लेने की नौबत आ सकती है। फिलहाल असीम मुनीर की कूटनीतिक सक्रियता इसी संतुलन को साधने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। आने वाले समय में पाकिस्तान का रुख यह तय करेगा कि पश्चिम एशिया का यह संकट कितना व्यापक रूप लेता है। हालांकि सैन्य इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान की सेना आज तक किसी युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकी है। भारत के साथ हुए युद्धों सहित कई सैन्य टकरावों में पाकिस्तान को करारी हार ही मिली है। ऐसे में यदि पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन में किसी संघर्ष में उतरता भी है तो उससे युद्ध के व्यापक परिदृश्य में कोई बहुत बड़ा सामरिक बदलाव आने की संभावना कम ही है।

नीतीश कुमार की नई सधी हुई बिहारी चाल के सियासी निहितार्थ

कमलेश पांडे

राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि भाजपा की सलाह पर यह निर्णय लिया गया लगता है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी (89 सीटें) बन गई है।

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत के चाणक्य श्री कुमार ने भाजपा के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी केंद्रीय राजनीतिक संभावनाओं को उभारने के लिए दिल्ली कूच करने का अप्रत्याशित फैसला लिया है। भले ही उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय बिहार की राजनीति में अपेक्षित एक बड़े बदलाव के हिस्से के रूप में लिया है, लेकिन यह भी उनकी लंबे समय से चली आ रही एक अधूरी इच्छा को प्रकट/पूरा करता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, भाजपा के ओबीसीकरण के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर सवर्णों की भाजपा नीत एनडीए से बेरुखी से उपजी सियासी परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए ही उन्होंने यह नया कदम उठाया है, जिसे एक तीर से कई निशाने के तौर पर देखा जाने लगा है। देश की समाजवादी राजनीति में भी अब उनका कोई निकट प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। इसलिए, गुरुवार, 5 मार्च 2026 को राज्यसभा की सदस्यता हेतु नामांकन दाखिल करने के साथ ही उनका अब नया भविष्य भी जुड़ा है।

समझा जाता है कि नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्यता की पुरानी 'अधूरी हसरत' अब पूरी हो रही है, क्योंकि वे विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा तो रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा नहीं। वहीं, राज्यसभा सदस्य बनने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, उपप्रधामंत्री, उपसभापति, कद्दावर केंद्रीय मंत्री बनने की उनकी नई सम्भावनाएं बनेंगी। वहीं राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए भी उनका यह कदम देखा जा रहा है, जहां वे बिहार, सामाजिक न्याय और विकास मुद्दों पर प्रभाव डाल सकें।

राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि भाजपा की सलाह पर यह निर्णय लिया गया लगता है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी (89 सीटें) बन गई है। इससे बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना आसान हो सकता है, जबकि नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि, जदयू में उनके इस फैसले पर असंतोष है, लेकिन इसे उनका व्यक्तिगत निर्णय बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का 'मास्क' हटाने का प्रयास मान रहा है। इससे राजद को पुनः सियासी ऑक्सीजन मिल सकता है। यूँ तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री की घोषणा अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुई है, क्योंकि यह प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव के परिणाम (16 मार्च 2026) के बाद शुरू होगी। एनडीए में बीजेपी का सबसे बड़ा दावा माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास 89 विधायक हैं।

हालांकि, संभावित उम्मीदवार के तौर पर सम्राट चौधरीः वर्तमान डिप्टी सीएम और भाजपा विधायक दल नेता, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। उनके पास गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं और राजनीतिक अनुभव समृद्ध है। वहीं, विजय कुमार सिन्हाः उपमुख्यमंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सम्राट से थोड़ा पीछे हैं। वहीं नित्यानंद रायः केंद्रीय मंत्री, BJP से प्रमुख नाम हैं, लेकिन नया चेहरा भी संभव है। अन्य चर्चाएंओं में नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र चुनावी आधार नहीं है।

जदयू नेता विजय चौधरी ने पुष्टि की कि भाजपा से ही मुख्यमंत्री बनेगा। यह बदलाव एनडीए की आंतरिक रणनीति का हिस्सा लगता है। इससे भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रभावित होगा। वहीं, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का विचार मुख्य रूप से नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए उठाया जा रहा है। वे लो-प्रोफाइल जीवन जीते रहे हैं, लेकिन पिता के राज्यसभा जाने के बाद जदयू में उनकी एंट्री तय मानी जा रही है।

जहां तक राजनीतिक रणनीति की बात है तो नीतीश के राष्ट्रीय स्तर पर जाने से बिहार में भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलेगा, जबकि निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर जदयू का प्रभाव कायम रहेगा। हालांकि एनडीए की बैठक में इस पर मुहर लगने की चर्चा है, जो सत्ता समीकरण को संतुलित करेगी। वहीं निशांत अब तक सियासत से दूर रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति पिता की लंबी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह कदम जदयू कार्यकर्ताओं को एक नया चेहरा देकर पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से है। इसके अलावा मोदी के हनुमान लोजपा कोटे से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सियासत को चमकाने के लिए भी यह नया फेरबदल संभावित प्रतीत होता है।

टिप्पणी

न्यायिक उत्तर ढूंढना आलसी नजरिया

बदले राजनीतिक माहौल में अदालतें न्यायिक सक्रियता दिखाने में खुद को असमर्थ पा रही हैं, तो समाज का एक हिस्सा इसे दायित्व निर्वहन से मुंह मोड़ना मानेगा। बहरहाल, संदेश यही है कि राजनीतिक प्रश्नों का न्यायिक उत्तर ढूंढना आलसी नजरिया है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने स्वीकार किया है कि कथित गौ-रक्षकों की अवैध गतिविधियों और भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो 'सामान्य दिशा-निर्देश' जारी किए, उनकी निगरानी कोर्ट के लिए संभव नहीं रह गई है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए थे। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा था कि नस्ल, जाति, वर्ग या धर्म का बिना ख्याल किए सभी नागरिकों की ऐसे अपराधों से रक्षा करना सरकार का दायित्व है।

बेंच ने ऐसी घटनाओं को रोकने, पीड़ितों से इंसाफ और मुजरिमों को दंडित करने के लिए कई उपाय तय किए। सरकारों से कहा गया कि इन उपायों पर अमल कर वे सुप्रीम कोर्ट में अनुपालना रिपोर्ट पेश करें। जाहिर है, ऐसा नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद उस तरह की घटनाएं जारी रहीं। उनका ही जिक्र करते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की गुजारिश की गई। तभी कोर्ट ने कहा था कि विभिन्न स्थलों और विभिन्न राज्यों में हुई मॉब लिंचिंग एवं हिंसा की 'सूक्ष्म निगरानी' करना उसके लिए संभव नहीं है। यही बात जस्टिस सूर्य कांत दोहराई है।

कहा है कि अदालत को ऐसे मामलों में 'सामान्य दिशा-निर्देश' देने के बजाय हर मामले पर अलग सुनवाई करनी चाहिए। इस तरह चीफ जस्टिस ने अदालती दायरे की पुनर्व्याख्या की है। संवैधानिक नजरिए से इसमें खोट नहीं निकाली जा सकती। मगर अतीत में खुद न्यायालयों ने स्वतः संज्ञान के जरिए संवैधानिक भावना की रक्षा की भूमिका अपनाई थी। इसे 'न्यायिक सक्रियता' कहा गया। मगर बदले राजनीतिक माहौल में अदालतें इस भूमिका को अपनाए रखने में खुद को असमर्थ पा रही हैं, तो नागरिक समाज का एक हिस्सा इसे दायित्व निर्वहन से न्यायपालिका के मुंह मोड़ने के रूप में देखेगा। बहरहाल, उन समूहों के लिए संदेश यही है कि राजनीतिक प्रश्नों का न्यायिक उत्तर ढूंढना आसान एवं आलसी नजरिया है। वैसे समाधान असल में सार्वजनिक जीवन की धूल-धक्कड़ में उतर कर ही खोजे जा सकेंगे।

ब्लॉग

औषधीय और सुगंधित पौधेः स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण

डब्ल्यूडब्ल्यूडी को सीआईटीईएस (वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौते) को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूडी 2026 का विषय औषधीय और सुगंधित पौधेः स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण है, जो स्वास्थ्य और आजीविका के लिए पादप संबंधी संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

लगभग 15,000 औषधीय पौधों की प्रजातियों के साथ भारत जैव विविधता से समृद्ध 17 विशाल देशों में से एक है। इनमें से 8,000 का उपयोग भारतीय औषधियों में किया जाता है जिससे यह औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया है।

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली की ओर से संरक्षित 9,361 औषधीय और सुगंधित पौधों के साथ भारत प्राकृतिक पर्यावास और उससे बाहर विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों के माध्यम से सक्रिय रूप से औषधीय और सुगंधित पौधों को नष्ट होने से बचाने में लगा हुआ है। विश्व में प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वन्य जीवों और वनस्पतियों के सम्मान और लोगों तथा पृथ्वी के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित यह दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौते (सीआईटीईस) को स्वीकार करने का प्रतीक है जो यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है कि वन्यजीवों से संबंधित व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है। यह दिवस इस बात को रेखांकित करता है कि वन्यजीव न केवल प्रकृति की सुंदरता का हिस्सा हैं बल्कि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका, जलवायु परिवर्तन से निपटने की सामर्थ्य और सतत विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ऐसे समय में जब जैव विविधता को वन्यजीवों के निवास स्थान के विनाश, अत्यधिक शोषण, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है तब विश्व वन्यजीव दिवस वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जैविक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी रूप से उपयोग करने के लिए एक वैश्विक आह्वान है।

विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का विषय - औषधीय और सुगंधित पौधेः स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण - दवाइयों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधों के महत्व, सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने में उनकी भूमिका और स्थानीय समुदायों को उनसे होने वाली आय पर बल देता है। संपूर्ण विश्व में विकासशील के 70-95 प्रतिशत लोग आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पारंपरिक औषधियों पर निर्भर करते हैं जिसमें से अधिकतर पौधों से मिलने वाले संसाधनों से प्राप्त होती हैं। औषधीय और सुगंधित पौधे पारंपरिक औषधीय प्रणाली की नींव हैं और आधुनिक दवा निर्माण उद्योग में भी अहम योगदान देते हैं। स्वास्थ्य के लिए उपयोग के अतिरिक्त ये पौधे परागण के लिए कीट और पक्षियों की सहायता करके, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर और जैव विविधता को बढ़ाकर पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करते हैं। इसलिए उनका संरक्षण विशेष रूप से भारत जैसे से भरपूर देशों के लिए वैश्विक प्राथमिकता का विषय है। वन्यजीव दिवस 2026 का विषय भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत जैव विविधता से समृद्ध विश्व के 17 विशाल देशों में से एक है और विश्व की जैव-विविधता का 7 प्रतिशत भाग इसी देश में है। यहां 15 कृषि-जलवायु क्षेत्र, 45,000 विभिन्न पौधों की प्रजातियां हैं जिनमें से 15,000 औषधीय पौधे हैं। इनमें से लगभग 8,000 प्रजातियों का उपयोग भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और लोक चिकित्सा प्रणालियों में किया जाता है। भारत के लगभग 70 प्रतिशत औषधीय और सुगंधित पौधे (एमएपी) पश्चिमी और पूर्वी घाट, हिमालय और अरावली क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने 5,250 से अधिक पौधों की प्रजातियों की पहचान की है और विभिन्न रोगों के संबंध में उपयोग के लिए 9,567 से अधिक लोक दावों का प्रलेखण किया है। भारत इस समृद्ध विरासत की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की ओर से औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए समर्पित योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और विपणन में सहायता प्रदान की जाती है। ये प्रयास औषधीय पौधों की अपनी समृद्ध विरासत की सुरक्षा के लिए भारत की मजबूत और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत ने औषधीय और सुगंधित पौधों की अपनी समृद्ध विरासत को बचाने के लिए मजबूत और कई स्तरों वाला तरीका अपनाया है। प्राकृतिक पर्यावासों में यथास्थान (इन-सीटू) संरक्षण का अर्थ है पौधों और जानवरों को उनकी उत्पत्ति के प्राकृतिक स्थलों पर सुरक्षित रखना। यह कार्य राष्ट्रीय उद्यानों, बायोस्फीयर रिजर्व और जीन अभयारण्यों के माध्यम से किया जाता है। औषधीय पौधों के लिए इस तरह के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र पहल (एमपीसीए) है। एमपीसीए एक नामित स्थल है जिसका उद्देश्य औषधीय पौधों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना है। वर्तमान में भारत में 108 एमपीसीए साइट हैं जो यथास्थान (इन-सीटू) संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके जैविक और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ स्वदेशी स्वास्थ्य परंपराओं को लागू करने के लिए उपयुक्त मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक्स-सीटू संरक्षण का अर्थ है अपने प्राकृतिक आवासों के बाहर नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों के आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा करना ताकि दीर्घकालिक रूप से संरक्षण और जंगलों में संभावित रूप से उन्हें पुनः लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। भारत में, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बीज जीन बैंक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली में 9,361 औषधीय और सुगंधित पौधों (एमएपी) का संरक्षण शामिल है। इन एक्स-सीटू विधियों का उपयोग खराब बीजों की उत्पत्ति या वानस्पतिक प्रसार वाली प्रजातियों के लिए किया जाता है। साथ में, वे भविष्य में उपयोग के लिए औषधीय पौधों की विविधता को सुरक्षित करने में मदद करते हैं।

सरकार ने देश भर में औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख योजनाएं और पहल शुरू की हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) आयुष मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया गया है। यह फसलों की विविधता में सहायता करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि प्रणालियों के साथ जोड़कर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देता है। यह मिशन गुणवत्ता में सुधार और मूल्य वर्धित आयुष उत्पादों के संबंध में सहयोग के लिए अच्छी कृषि और संग्रह के तौर-तरीकों (जीएसीपी) का पालन करते हुए खेती को प्रोत्साहित करता है।

एनएएम आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण को भी मजबूत करता है, उनके लिए कच्चे माल की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करता है और एक औषधीय पौधों के मजबूत क्षेत्र को विकसित करने के लिए अनुसंधान, प्रसंस्करण और विपणन में सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती और विपणन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों की पहचान करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। यह अधिक लोगों को औषधीय पौधों को बचाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह योजना भारत सरकार की ओर से एनएमपीबी के माध्यम से औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की स्थापना करके उनके प्राकृतिक पर्यावासों में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का परिव्यय 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 322.41 करोड़ रुपये है। संरक्षण की पहल को अवक्रमित और ग्रामीण भूमि पर वृक्षारोपण में सहयोग करके भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें अनुसंधान और गुणवत्ता के आश्वासन पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है जिन्हें देश भर में जीएसीपी और अपरिष्कृत दवा भंडार के माध्यम से सहयोग मिलता है। ई-चरक पोर्टल किसानों को बाजारों से जोड़ता है और पूरे भारत में 25 जड़ी-बूटी बाजारों से अद्यतन मूल्य की जानकारी प्रदान करता है। एमएसपी तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके औषधीय पौधों की उपज के लिए उचित मूल्य मिले, टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित किया जाए और वन्य स्रोतों पर दबाव कम किया जाए।

छात्रों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर जड़ी-बूटियों के हर्बल गार्डन को बढ़ावा दिया जाता है। दैनिक जीवन में औषधीय पौधों के महत्व को उजागर करने के लिए रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया पर विशिष्ट प्रजातियों से जुड़े मल्टीमीडिया अभियान भी चलाए जाते हैं। पूर्व सैनिकों और प्रादेशिक सेना के कर्मियों को शामिल करते हुए इको टास्क फोर्स तंत्र महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की उत्पत्ति के प्राकृतिक स्थानों को पुनर्जीवित करने और उनका पुनर्वास करने में लगा हुआ है। प्रत्येक इको टास्क फोर्स प्रति वर्ष कम से कम 400 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य करता है जिसमें देशी औषधीय पौधों की प्रजातियों का न्यूनतम 60 प्रतिशत रोपण होता है। यह योजना संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, वन पंचायतों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करती है। यह स्थानीय समुदायों को औषधीय पौधों के मूल्य संवर्धन, जैव पदार्थों को सुखाने, उनके भंडारण और विपणन में मदद करता है जिससे उनकी आजीविका में सीधे सुधार होता है। एनएमपीबी खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर औषधीय पादप संरक्षण को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्य करता है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है और भारत के पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए काम करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक समझौतों के अंतर्गत उचित तरीके से लाभ साझा किया जाए।

एक दुल्हन, दो दूल्हे, फिर भी हाथ नहीं हुए पीले, दोनों ही बरात वापस लौटी, इसलिए फिरा अरमानों पर पानी

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर जिले के खतौली इलाके के एक गांव में शादी की तैयारियां दो बरात पहुंच जाने के कारण खटाई में पड़ गई। घराती और बराती उलझे मसले को सुलझाने में जुटे थे इसी बीच चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पहुंच गई। दुल्हन की उम्र को लेकर विवाद बढ़ गया।

इस कारण दूल्हों को बिना फेरे लिए ही लौटना पड़ गया। वहीं, दुल्हन को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। चिकित्सीय परीक्षण के बाद दुल्हन की उम्र तय होगी। दुल्हन के पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी छह माह पहले शामली के गांव बाबरी निवासी प्रदीप उर्फ अनिल के साथ तय की थी। शादी से एक दिन पहले सोमवार को दूल्हे के भाई का निधन हो गया। बरात पर दूल्हे पक्ष ने कहा कि वह बताएंगे कि समय बढ़ाना है या बरात आएगी। इस बीच दूल्हे पक्ष की ओर से सोमवार को कोई अंतिम सूचना दुल्हन पक्ष को नहीं दी गई।

सोमवार शाम को ही रिश्ता तय किया

दुल्हन के बाबा मनोहर ने तैयारियों को देखते हुए मेरठ के थाना मेडिकल के गांव डिग्गी निवासी आकाश के साथ सोमवार शाम को ही रिश्ता तय कर दिया। शर्त रखी कि बरात मंगलवार को ही आएगी।

दुल्हन को नाबालिग बताते हुए चाइल्ड हेल्प लाइन को किया कॉल

मंगलवार को शामली और मेरठ से दोनों दूल्हे बरात लेकर पहुंच गए। इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव कराने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान किसी ने दुल्हन को नाबालिग बताते हुए चाइल्ड हेल्प लाइन को कॉल कर दी।

आयु प्रमाणपत्र नहीं दिखा पाए परिजन

चाइल्ड हेल्प लाइन प्रभारी सचिन कुमार, सुपरवाइजर भुवनेश्वर टीम के साथ गांव पहुंच गए। परिजन टीम को आयु प्रमाणपत्र नहीं दिखा सके। इसके बाद टीम दुल्हन को अपने साथ लेकर चली गई। चाइल्ड हेल्प लाइन प्रभारी ने बताया कि लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। फिलहाल जिला अस्पताल के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। यहां पर ओसिफिकेशन टेस्ट से लड़की की उम्र तय होगी। इसके बाद दोबारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

उम्र का पेच फंसते ही लौट गए दूल्हे

दुल्हन की उम्र का पेच फंसते ही दोनों दूल्हे अपनी बरात लेकर लौट गए। शामली और मेरठ की बरात में सात-सात बराती आए थे। पुलिस ने कहा कि दोनों बरात वापस भिजवा दी गई है।

पूरा परिवार दिव्यांग, ग्रामीण कर रहे थे शादी

दुल्हन पक्ष का पूरा परिवार दिव्यांग है। माता-पिता के अलावा भाई-बहन भी दिव्यांग हैं। ऐसे में शादी की पूरी तैयारी आसपास के लोग ही कर रहे थे। अब उम्र का फैसला हो जाने के बाद ही शादी पर निर्णय होगा।

दूल्हे के हंगामा करने पर दुल्हन ने लौटा दी बरात

वहीं, एक दूसरा मामला भी मुजफ्फरनगर में ही सामने आया है। मंसूरपुर इलाके के अजमतगढ़ गांव में सोमवार शाम डीजे पर नृत्य को लेकर हुए विवाद के बाद दुल्हन ने फेरे लेने से इन्कार कर दिया। देर रात 4.50 लाख रुपये के समझौते के बाद बरात बिना दुल्हन के लौट गई। शामली के बनत से आई बरात में चढ़त के दौरान डीजे पर डांस को लेकर बरातियों में झगड़ा हो गया। मारपीट में कई बराती घायल हुए। जब लड़की पक्ष के लोग समझाने गए तो कुछ बरातियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें दूल्हा भी शामिल था। इसके बाद लड़की पक्ष ने फेरे देने से मना कर दिया और बरात को बंधक बना लिया। देर रात लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष को 4.50 लाख रुपये नकद दिए, जिसके बाद बरात बिना दुल्हन के लौट गई। पुलिस ने इस मामले में किसी भी जानकारी से इन्कार किया है।

जिले को मिली सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी किशोरियों को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने बताया कि यह टीकाकरण अभियान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम से अलग एक विशेष राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जाएगा। इसमें गार्डासिल नाम की क्वाड्रिवैलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक खुराक दी जाएगी, जो एचपीवी के टाइप 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है। यही वायरस सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारण माने जाते हैं। इसके अलावा यह टीका टाइप 6 और 11 से भी बचाव करता है। विशेषज्ञों के अनुसार 14 वर्ष की आयु में एक डोज लगाने से लंबे समय तक मजबूत सुरक्षा मिलती है। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर वर्ष लगभग 80 हजार नए मामले सामने आते हैं, जबकि 42 हजार से अधिक महिलाओं की मौत इस बीमारी से हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एचपीवी वैक्सीन 93 से 100 प्रतिशत तक प्रभावी मानी जाती है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। वर्ष 2006 से अब तक दुनियाभर में 60 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। कई देशों में इस टीकाकरण के बाद एचपीवी संक्रमण और सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह टीकाकरण पूरी तरह मुफ्त और स्वैच्छिक होगा, ताकि सभी वर्गों की किशोरियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

ज़िंक–ओआरएस के साथ डायरिया से डर नहीं : डॉ. फारुख अहमद

आर्यावर्त संवाददाता

फ़िरोज़ाबाद। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई। पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) एवं केनव्यू के सहयोग से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. फारुख अहमद ने कहा कि- ज़िंक-ओआरएस के साथ डायरिया से डर नहीं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

इस मौके पर प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि डायरिया से डर नहीं कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा कार्यकर्ताओं, आशा संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएसआई इंडिया के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही डायरिया रोको अभियान (स्टॉप डायरिया कैम्पेन) के दौरान ई रिक्शा के माध्यम से डायरिया से बचाव और प्रबन्धन के बारे में प्रचार-प्रसार किया गया है। जनपद के विभिन्न स्थानों पर दीवार लेखन कराया गया है। प्रचार-प्रसार के तहत ही रैली निकाली गयी है और स्कूल गतिविधियों में पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में डायरिया से बचाव के सन्देश पहुंचाए गए हैं।

समीक्षा बैठक में पीएसआई इंडिया के प्रतिनिधि राजेश कुमार प्रजापति ने अब तक की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। हेल्थ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) की रिपोर्ट की भी समीक्षा की गयी। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (डीपीएम) भानु प्रताप सिंह ने रिपोर्टिंग में सुधार के बारे में चर्चा की। डीसीपीएम रवि कुमार ने बेहतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। शहरी स्वास्थ्य समन्वयक प्रबल प्रताप सिंह ने डायरिया कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों की वजह से होने वाले सुधार के बारे में चर्चा की साथ ही यूपीएचसी पर बनाए गए ओआरएस एवं ज़िंक कार्नर को लेकर चर्चा की। डिवीज़नल अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर इरशाद अहमद ने कहा कि डायरिया की पहचान समय पर होना और आवश्यक उपचार मुहैया कराना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट एफपीएलएमआईएस मैनेजर अरविन्द चोधरी, जिला महिला अस्पताल के प्रतिनिधि, बीपीएम, बीसीपीएम, फार्मासिस्ट, एचएमआईएस आपरेटर और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ग्लूकोमा आंख की गंभीर बीमारी है समय-समय पर जांच करना जरूरी डॉ रवि त्रिपाठी

सुलतानपुर। जनपद के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर रवि त्रिपाठी नंदनी आई केयर जेल रोड सुलतानपुर ने एक भेंट में बताया कि ग्लूकोमा आँखों की एक गंभीर बीमारी है जो आँख के अंदर दबाव बढ़ने के कारण आँख की नस को नुकसान पहुँचाती है। यह स्थायी अंधत्व का एक प्रमुख कारण है। इसे अक्सर साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। धीरे-धीरे साइड की दृष्टि कम होना, धुंधला दिखाई देना, रोशनी के चारों ओर घेरा दिखाई देना, आँखों में दर्द या सिरदर्द, कुछ मामलों में अचानक दृष्टि में कमी 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जिनके परिवार में ग्लूकोमा का इतिहास हो, मधुमेह या उच्च रक्तचाप के रोगी, लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाओं का उपयोग करने वाले। नियमित नेत्र जांच से ग्लूकोमा का समय पर पता लगाया जा सकता है।

शाहजहांपुर में हाईवे पर रोडवेज बस और कार की भीषण भिड़ंत, लखीमपुर के तीन युवकों की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के अल्हागंज थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। बरेली फर्रुखाबाद हाईवे पर सुगसुगी मोड़ से पहले रोडवेज बस और कार की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 30 वर्षीय अरुण, 32 वर्षीय ऋषभ और 30 वर्षीय संजय की मौत हो गई। तीन युवक लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी क्षेत्र के मुड़ा खालसा अमीन नगर के निवासी थे। दो लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मौके पर ही तीनों युवकों की मौत

पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह करीब सात बजे बरेली डिपो की रोडवेज बस और कार के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार अरुण, ऋषभ और संजय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनिल और गौरव निवासी मूड़ा भाई छतौनिया, थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें फर्रुखाबाद रेफर कर दिया गया।

मार्ग पर यातायात रहा प्रभावित

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया गया है कि सुबह के वक्त घना कोहरा था। आशंका है। कोहरे के कारण ही हादसा होने की आशंका जताई गई है। हादसे के बाद कुछ समय तक मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि तहरीर आने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सक ने बता दिया था मृत, सड़क के गड्ढे ने लौटा दीं सांसें, विनीता को मिली नई जिंदगी

आर्यावर्त संवाददाता

पीलीभीत। बरेली के अस्पताल से ब्रेन डेड घोषित पीलीभीत शहर निवासी महिला की सांसें सड़क के गड्ढे के कारण लगे झटके से लौट आईं। परिजन उन्हें एंबुलेंस से घर वापस ले जा रहे थे। सड़क पर गड्ढे की वजह से गाड़ी में झटका लगा। इस दौरान महिला मरीज की सांसें लौट आईं। रोत-बिलखते परिजनों के चेहरों पर नई उम्मीद जागी। महिला को आननफानन शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां करीब आठ दिन उपचार के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गईं हैं।

शहर निवासी विनीता शुक्ला जिला न्यायालय में लिपिक पद पर कार्यरत हैं। 22 फरवरी को उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। वह बेहोश होकर गिर गईं। उनके पति कुलदीप शुक्ला ने बताया कि विनीता को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने सांस न आने की बात कही और 24 फरवरी को ब्रेन डेड बताकर वेंटिलेटर से हटा दिया। परिजन उन्हें लेकर पीलीभीत आ रहे थे।

एक झटके में लौट आईं सांसें

पीलीभीत-बरेली मार्ग पर हाफिजगंज के समीप एंबुलेंस का पहिया सड़क के गड्ढे में गिरा, जिसे झटका लगने से विनीता के शरीर में हलचल हुई और उनकी सांस लौट आईं। परिजन उन्हें लेकर शहर के निजी अस्पताल पहुंचे। जहां न्यूरो चिकित्सक ने उनका इलाज किया। करीब आठ दिन बाद विनीता ठीक होकर घर आ गई हैं। पति कुलदीप शुक्ला ने बताया कि सड़क के गड्ढे से लगे झटके से सांस लौटी हैं। यह भगवान का चमत्कार ही है।

अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे परिजन

अस्पताल में ब्रॉड डेड घोषित होने की जानकारी पर घर में अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे थे। कुलदीप शुक्ला ने बताया कि उनके पैतृक घर पुवायां और अन्य स्थानों से रिश्तेदार भी घर आ गए थे।

स्कूल का वार्षिक महोत्सव मनाया गया

सुलतानपुर। विवेक नगर स्थित दिल्ली मॉन्टेसरी स्कूल का वार्षिक महोत्सव मनाया गया जिसमें नर्सरी से कक्षा-8 तक के बच्चों ने कई मनभावन कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अमिता विद्यार्थी एवम मैनेजर सुधीश विद्यार्थी ने दीप जला कर किया और सरस्वती वंदना के उपरान्त कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों ने फैन्सी ड्रेस कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिसमें वे डॉक्टर, सैनिक, कानून, पुलिस, योगी, इंदिरा गाँधी सुपर मॉम आदि बनकर आए थे और उन्होंने सबको अचंभित कर दिया। जिसमें अभित्या, गौरवी, शाश्वत, भाव्या, हर्ष, नित्या, कुश, रुद्रांश, मो. बिलाल, रुवादिश अंसारी, अनय मिश्रा आदि बच्चों ने मनभावन प्रस्तुति पेश किया। कक्षा-1 से 8 तक के बच्चों में वेदांशी राय, शुभांगी शुक्ला, कलश, कर्निका पाण्डेय, आयु, आकांक्षा आदि बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

गर्मी में सर्दी वाला कोहरा, जानिए क्यों बदला मौसम का मिजाज, विशेषज्ञ ने बताया कार

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। बरेली समेत आसपास के जिलों में मौसम के अजब रंग देखने को मिल रहे हैं। बरेली में शहर से लेकर देहात तक बुधवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम रही। इसके कारण सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चले। इससे पूर्व मंगलवार को भी सुबह के वक्त कोहरा छाया और दिनभर धुंध रही। बदायूं, शाहजहांपुर जनपद के कई इलाकों में भी कोहरा छाया रहा। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आगामी तीन-चार दिनों तक सुबह के वक्त कोहरा और दिन में धुंध छाए रहने की संभावना है।

15 मार्च से हल्की बारिश के आसार

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल अग्रवाल के मुताबिक प्रदेश के निचले क्षोभमंडल में आ रही आर्द्र पुरवा हवा में नमी की अधिकता के कारण सुबह के समय कोहरे के साथ-साथ दिन में धुंध की स्थिति बन रही हैं। आगामी तीन-चार दिनों में मौसम अत्यधिक गर्म रहने तथा कोहरा/धुंध की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके बाद आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 मार्च से प्रदेश के तराई इलाकों के साथ-साथ पूर्वांचल के कुछ भागों में इस सीजन में पहली बार बारिश होने के साथ-साथ तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है।

बदायूं जिले में भी छाया रहा कोहरा

बदायूं जिले में सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ दूरी तक ही दिखाई दे रहा था। ऐसे में वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर और धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। खासकर हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहन चालक सावधानी के साथ सफर करते नजर आए। कोहरे के कारण सुबह टहलने निकलने वाले लोगों और राहगीरों को भी आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन पर हल्का असर दिखाई दिया। मौसम में इस बदलाव के कारण लोगों को सुबह के समय ठंडक का एहसास भी हुआ। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही धीरे-धीरे कोहरा छंट गया और धूप निकलने से मौसम सामान्य हो गया।

यूजीसी, सवर्णों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी, यूपी में फिर फतह हासिल करने को ये है आरएसएस–भाजपा का नया फार्मूला

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के लिए भाजपा ने नया फार्मूला तैयार किया है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भी सहमति बताई जा रही है। मिशन यूपी 2027 को फतह करने की राह में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा।

इसमें संगठन विस्तार से लेकर कार्यकर्ताओं को सरकार में समायोजित करने का फुलप्रूफ फॉर्मूला तैयार किया गया है। इससे विभिन्न जातियों छत्रपों के साथ ही नाराज व निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को भी मनाया जाएगा। यूजीसी एक्ट से उपजी सवर्ण जातियों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश जारी है।

2027 के विधानसभा चुनाव में अधिक समय नहीं होने के कारण भाजपा और आरएसएस अपने स्तर पर सक्रिय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ संघ पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करने निकले हैं। पांच मार्च को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की समन्वय बैठक में भाग लिया। इस दौरान सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक और संघ पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए। इस दौरान सरकारी कामकाज की दिक्कतें भी मुख्यमंत्री के सामने उठाई गई। मुख्यमंत्री की सक्रियता से चुनावी माहौल तैयार हो रहा है।

यूजीसी एक्ट के बाद विरोध के माहौल से मची खलबली

भाजपा के कैडर वोटर में सवर्ण जातियां शामिल है। यूजीसी एक्ट के बाद जिस तरह से सवर्ण जातियों ने विरोध का बिगुल बजाया है, उससे भाजपा में खलबली मची है। कोई भी भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि यूजीसी एक्ट पर सीधा जवाब नहीं दे रहा है, जबकि युवाओं में आक्रोश धीरे-धीरे पनप रहा है। आरएसएस की ओर से भाजपा को इस ओर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में भाजपा नेता व जनप्रतिनिधि इस मामले को कोर्ट में बताकर माहौल को बदलने की कोशिश में भी जुटे हैं। भाजपा की मंशा इस विरोध को आंधी बनने से रोकने की है।

संगठन और सरकार में शीघ्र ही समायोजित होंगे नेता

चुनाव में बहुत कम समय बचने के कारण भाजपा तेजी से कदम उठा रही है। पिछले एक साल से अधिक समय से चल रहे संगठन चुनाव शीघ्र ही पूरे होंगे। इसमें नए क्षेत्रीय अध्यक्षों को घोषणा, क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन, जिला व महानगर कार्यकारिणी का गठन, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करके पार्टी नेताओं को समायोजित किया जाएगा। संगठन में समायोजित होने से बचने वाले नेता अतिशीघ्र पार्षद व सभासद मनोनीत होंगे। विभिन्न आयोगों, बोडों, समितियों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बनाया जाएगा।

जातीय समीकरणों पर दिया जाएगा पूरा ध्यान

भाजपा अपनी पूरी सोशल इंजीनियरिंग का परिचय संगठन विस्तार में देगी। यूजीसी एक्ट से नाराज सवर्ण समाज के नेताओं को संगठन में अहम पदों पर वरीयता दी जाएगी। दलित, ओबीसी, महिला वर्ग को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की तैयारी की जा रही है। भाजपा नेताओं को जिला पर्यवेक्षक के रूप में भेजकर कोर कमेटियों से पार्षद, सभासद मनोनयन और जिला कार्यकारिणी में शामिल होने वाले नेताओं के नामों का पैनल तैयार किया जा चुका है। यह पैनल प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच भी चुका है। पार्टी की मंशा 20 मार्च तक अपना कार्य पूरा करने की है।

पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि भी अड़े

भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार फॉर्मूले के तहत ही पार्टी संगठन के गठन की कार्यवाही चल रही है। इससे इतर पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने समर्थकों को जिला, क्षेत्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल कराने में जुटे हैं। इसके लिए प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक सिफारिशें की जा रही है। आरएसएस के पदाधिकारी भी अपने इसमें पैरवी करने में जुटे हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी भाजपा नेताओं की निगाह लगी हुई है।

आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। सोशल मीडिया पर एक विशेष समुदाय के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शहजाद अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सीओ सिटी सौरभ सामंत को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें समाज कल्याण विभाग सुल्तानपुर में तैनात कनिष्ठ सहायक अभिषेक गिरी द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक विशेष समुदाय के प्रति आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी की गई है। आरोप है कि इस प्रकार की टिप्पणी से समाज में आपसी सौहार्द बिगड़ने की आशंका है और संबंधित समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी पद पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा इस तरह की भड़काऊ व गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है और इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ उचित कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शहजाद अहमद, अशोक सिंह बिशेन, सुल्तान खान, पवन यादव, सईद अहमद, सुरेश कुमार गौतम और संजय यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शुगर-बीपी नहीं रहता कंट्रोल तो किडनी से भी धो बैठेंगे हाथ, लापरवाही पड़ न जाए भारी

जब डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं रहते, तो यही दोनों बीमारियां धीरे–धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में क्रॉनिक किडनी डिजीज के प्रमुख कारणों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन सबसे ऊपर हैं।

किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। भले ही ये अंग काफी छोटा है, लेकिन शरीर के कामकाज में इसकी बड़ी भूमिका होती है। किडनी रोजाना लगभग 130-130 लीटर खून को छानकर उसमें से जहरीले पदार्थ, मेटाबॉलिक अपशिष्ट जैसे यूरिय-क्रिएटिनिन) और अतिरिक्त पानी को निकालती है। किडनी की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम, पोटेशियम) का संतुलन बनाए रखने, रक्त के pH स्तर को नियंत्रित करने जैसे इस छोटे से अंग के कई बड़े-बड़े काम हैं।

हालांकि दुनियाभर में किडनी से संबंधित बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कम उम्र के लोगों में भी ये खतरा देखा जा रहा है। किडनी की समस्याओं पर अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इससे किडनी फेलियर तक का खतरा रहता है जिसे जानलेवा माना जाता है।

किडनी की बीमारियों के लिए लाइफस्टाइल-खानपान में गड़बड़ी को प्रमुख माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है तो इससे भी किडनी खराब होने का जोखिम काफी बढ़ सकता है?

किडनी की बीमारियों का खतरा

दुनियाभर में बढ़ती किडनी की बीमारियों को लेकर लोगों को शिक्षित और जागरूक करने और किडनी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर अलर्ट करने के उद्देश्य से हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार (इस बार 12 मार्च) को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। किडनी की बीमारियों के लिए कई कारणों को जिम्मेदार पाया गया है।

खान-पान में गड़बड़ी, ज्यादा सोडियम वाली चीजें खाना।

धूम्रपान-शराब की आदत।

अधिक वजन-मोटापा।

बार-बार पेनकिलर का इस्तेमाल।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इन जोखिम कारकों के अलावा जिन लोगों का शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ रहता है, उनमें धीरे-धीरे किडनी की दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। दुनिया भर में क्रॉनिक किडनी डिजीज के प्रमुख कारणों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन सबसे ऊपर हैं।

हाई शुगर के कारण किडनी की बीमारी

डॉक्टर कहते हैं, जिन लोगों का शुगर लेवल अक्सर बढ़ा हुआ रहता है उनमें किडनी की बीमारियों का खतरा अधिक हो सकता है।

लंबे समय तक हाई शुगर की समस्या किडनी की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है।

इससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी की समस्या हो सकती है।

लगातार हाई ग्लूकोज के कारण फिल्टरिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे पेशाब में प्रोटीन आने लगता है, इससे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है।

हाई ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक

हाई ब्लड शुगर की ही तरह से ब्लड प्रेशर भी रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की नाजुक नसें धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होने लग जाती हैं।

जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में नमक और पानी जमा होने लगता है, जिससे बीपी और बढ़ा रहता है।

जिन लोगों को हाई बीपी और हाई शुगर दोनों समस्याएं हैं, उनमें किडनी की बीमारी और इसके खराब होने का खतरा और भी ज्यादा होता है।

किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

किडनी रोग विशेषज्ञ बताते हैं, बीपी और शुगर के मरीजों को किडनी की सेहत को लेकर खास सावधानी बरतते रहना चाहिए। इन दोनों को कंट्रोल में रखकर आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में सुधार करना भी जरूरी है।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। इससे ब्लड प्रेशर, वजन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए एक चम्मच से कम नमक का सेवन करें।

किडनी को शरीर से गंदगी निकालने में मदद करने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें।

आहार में ताजे फल, सब्जियों और साबुत अनाज की मात्रा बढाएं।

प्रोसेस्ड, ज्यादा सोडियम वाले और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम या बिल्कुल न करें।

वजन को कंट्रोल रखें। मोटापा की स्थिति डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी की बीमारियों को बढ़ाने वाली हो सकती है।

धूम्रपान करने से किडनी में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, इसलिए धूम्रपान न करें।

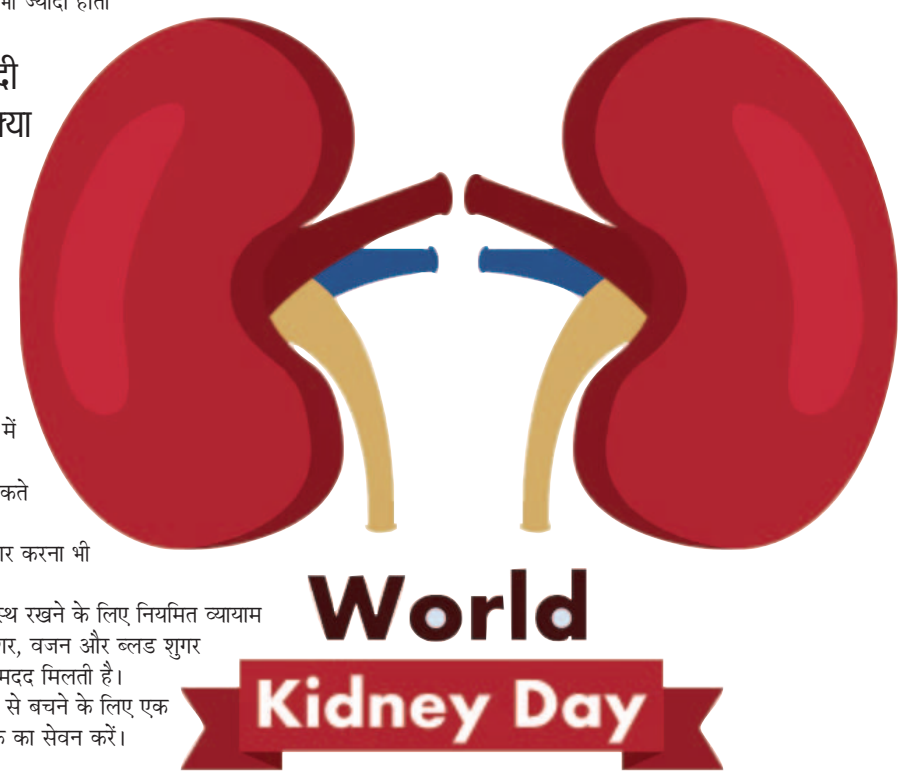

घर पर भी बनाया जा सकता है प्राकृतिक परफ्यूम, बस ध्यान में रखनी होंगी ये बातें

बाजार में वैसे तो ढेरों परफ्यूम मिलते हैं, लेकिन उनमें कई रसायम मिलाए जाते हैं। ऐसे में बेहतर होता है प्राकृतिक परफ्यूम लगाना। घर पर प्राकृतिक परफ्यूम बनाना एक कला है, जिसके जरिए आप अपनी व्यक्तिगत पसंद के मुताबिक खुशबू तैयार कर सकते हैं। जरूरी तेल, आधार तेल और दूसरी प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करके आप ऐसी खुशबू बना सकते हैं, जिसमें कोई बनावटी रसायन नहीं होंगे। इसके दौरान इन टिप्स का पालन करें।

आवश्यक तेल का ऐसे करें चुनाव

परफ्यूम के लिए आवश्यक तेल सबसे जरूरी सामग्री हैं। ऐसे तेल चुनें, जो एक-दूसरे के साथ अच्छे लगें और आपकी पसंद के भी हों। लोग लैवेंडर को मन शांत करने के लिए चुनते हैं, खट्टे फल वाले तेल ताजगी के लिए अच्छे होते हैं और गुलाब की खुशबू खास लगती है। अलग-अलग तेलों को मिलाकर आजमाएं, ताकि आप अपनी पसंद की खुशबू तलाश सकें। यह बात भी ध्यान रखें कि हर तेल की महक अलग होती है।

आधार तेलों को समझें

आधार तेल आवश्यक तेलों को पतला करते हैं और त्वचा पर लगाने में आसानी देते हैं। जोजोबा, बादाम और नारियल का तेल कुछ आम आधार तेल हैं। हर तेल की अपनी बनावट और खुशबू होती है, जिससे आखिरी खुशबू में फर्क आता है। जोजोबा तेल को कई लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यह त्वचा के प्राकृतिक तेल जैसा होता है और लगाने पर चिपचिपा नहीं लगता। ऐसा आधार तेल चुनें, जो आपके चुने हुए आवश्यक तेलों के साथ अच्छा लगे।

खुशबू की परतों पर दें ध्यान

परफ्यूम में आमतौर पर खुशबू की 3 परतें होती हैं: ऊपरी, बीच वाली और आखिरी परत। ऊपरी परत की खुशबू सबसे पहले नाक में आती है, लेकिन यह जल्दी ही खत्म हो जाती है। खट्टे फल या जड़ी-बूटियों जैसी खुशबू इस परत के लिए सही हैं। बीच वाली परत परफ्यूम की मुख्य खुशबू होती है। इनमें अक्सर फूलों या मसालेदार खुशबू होती है, जैसे लैवेंडर या दालचीनी। आखिरी परत खुशबू को गहराई देती है, जो देर से सामने आती है।

घर पर बने परफ्यूम हो ऐसे करें स्टोर

अपने घर के बने परफ्यूम को लंबे समय तक ताजा और खुशबूदार रखने के लिए उन्हें सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। अपने परफ्यूम को हमेशा कांच की काली बोतलों में रखें और उन्हें सीधी धूप से दूर रखें। धूप से आवश्यक तेलों की गुणवत्ता धीरे-धीरे खराब हो सकती है। साथ ही, इन्हें ठंडी जगहों पर रखें और हीटर या चूल्हे जैसी गरम चीजों से दूर रखें। ऐसी गर्मी से भी समय के साथ वे खराब हो सकते हैं।

हिचकी से परेशान हैं? इन 5 असरदार घरेलू नुस्खों को आजमाएं

हिचकी एक आम समस्या है, जो कभी भी हो सकती है। यह अक्सर अचानक से आती है और कई बार बहुत परेशान करती है। हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तेज खाना, ठंडा पेय पीना या पेट का फूलना। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप हिचकी को तुरंत रोक सकते हैं और इससे राहत पा सकते हैं।

नींबू का उपयोग करें

नींबू का खट्टा स्वाद दिमाग को उत्तेजित करता है और हिचकी को रोकने में मदद कर सकता है। एक छोटे से नींबू का रस निकालकर उसे धीरे-धीरे पीएं या फिर नींबू के टुकड़े को चूसें। इससे आपकी जीभ की नसें सक्रिय हो जाएंगी और हिचकी बंद हो सकती है। इसके अलावा नींबू का सेवन पाचन तंत्र को भी सुधारता है, जिससे पेट की गैस भी कम होती है और हिचकी से राहत मिलती है।

चीनी का सेवन करें

चीनी का मीठा स्वाद भी हिचकी रोकने में मदद कर सकता है। एक चम्मच चीनी को मुंह में डालकर धीरे-धीरे चूसें। इससे आपकी जीभ की नसें उत्तेजित होती हैं और हिचकी बंद हो सकती है। इसके अलावा चीनी का सेवन ऊर्जा भी देता है और आपकी मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है, जिससे हिचकी की समस्या जल्दी खत्म होती है। यह एक सरल और असरदार घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं।

ठंडा पानी पिएं

ठंडा पानी पीने से भी हिचकी जल्दी रुक सकती है। ठंडा पानी पेट को ठंडा करता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है, जिससे हिचकी बंद हो जाती है। इसके अलावा ठंडा पानी पाचन तंत्र को भी सुधारता है, जिससे पेट की गैस कम होती है और हिचकी से राहत मिलती है। एक गिलास ठंडा पानी धीरे-धीरे पिएं ताकि यह आपकी गले की नसों पर सही तरीके से असर कर सके।

सेब के सिरके का प्रयोग करें

सेब के सिरके का खट्टा स्वाद भी हिचकी रोकने में काम आ सकता है। एक चम्मच सेब का सिरका एक गिलास पानी में मिलाकर पीने से आपकी जीभ की नसें उत्तेजित होती हैं और हिचकी बंद हो जाती है। इसके अलावा सेब का सिरका पाचन तंत्र को भी सुधारता है, जिससे पेट की गैस कम होती है और हिचकी से राहत मिलती है। यह एक सरल और असरदार घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं।

ठंडी चीजें गले पर लगाएं

गले पर ठंडी चीजें लगाने से भी हिचकी रोकने में मदद मिलती है। बर्फ का टुकड़ा या ठंडा कपड़ा अपने गले पर हल्के से रगड़ें, इससे नसें उत्तेजित होती हैं और हिचकी बंद हो जाती है। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप आसानी से अपनी हिचकियों से राहत पा सकते हैं। अगली बार जब आपको हिचकी आए तो इन नुस्खों को आजमाएं और देखें कि इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे असरदार है।

Phone को 100% चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए? जानिए ऐसा करने से क्या होता है और कितने परसेंट तक चार्ज करना है सही

ज्यादातर लोग रात में फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह 100% चार्ज देखकर निकालते हैं। यह आदत आम है, लेकिन क्या ऐसा करना फोन की बैटरी के लिए सही है? आइए विस्तार से समझते हैं इस बारे में-

आज के समय में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। ज्यादातर लोग रात में फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह 100% चार्ज देखकर निकालते हैं। यह आदत आम है, लेकिन क्या ऐसा करना फोन की बैटरी के लिए सही है? क्या आपको अपने फोन को 100% तक चार्ज करना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं इस बारे में-

फोन को 100% चार्ज करना कितना सही?

आज के स्मार्टफोन में लिथियम-आयन की बैटरी होती है। समय के साथ हर बैटरी कमजोर होती है, चाहे आप कितना भी ध्यान रखें। लेकिन ज्यादा गर्मी और बार-बार 100% चार्ज करने से बैटरी जल्दी खराब हो सकती है।

जब फोन 80% से 100% जाता है, तब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर रोज ऐसा किया जाए, तो कई महीनों में बैटरी की क्षमता कम होने लगती है। हालांकि, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमेशा फोन को 100% चार्ज करना गलत नहीं है। फोन खुद इतना स्मार्ट होता है कि ओवरचार्ज न हो। आजकल iPhone और Android फोन में Optimised या Adaptive Charging जैसे फीचर मिलते हैं, जो बैटरी को अपने आप सुरक्षित रखते हैं। एक-दो बार या रोज भी 100% चार्ज करने से फोन तुरंत खराब नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैटरी लंबे समय तक अच्छी चले, तो थोड़ा ध्यान रखना फायदेमंद है।

फोन कितने परसेंट तक चार्ज करना सही है?

बैटरी को हेल्दी रखने के लिए फोन को- 20% से 80% के बीच चार्ज रखना सबसे बेहतर माना जाता है। इससे बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और लंबे समय तक बैटरी अच्छी परफॉर्मेंस देती है।

इन बातों का रखें ध्यान

अधिक सावधानी बरतने के लिए फोन को चार्ज करते समय गर्म जगह पर न रखें।

तकिए के नीचे रखकर फोन चार्ज न करें।

चार्जिंग के दौरान गेम न खेलें।

हमेशा अच्छी क्वालिटी और ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करें।

ध्यान रखें अगर आप हर 2-3 साल में फोन बदल लेते हैं, तो 100% चार्ज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फोन को 4-5 साल तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 80% तक चार्ज करने की आदत डालना फायदेमंद रहेगा। 100% चार्ज करना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसे रोज की आदत बनाना सही नहीं माना जाता है। इस तरह थोड़ी सी सावधानी से आप अपने फोन की बैटरी को ज्यादा समय तक अच्छा रख सकते हैं।

बैंक में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, आईडीबीआई में 1100 पदों पर बंपर भर्ती शुरू

कहीं छूट न जाए तारीख- तुरंत करें अप्लाई

नई दिल्ली, एजेंसी। बैंकिंग सेक्टर में बेहतरीन करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई बैंक) लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के कुल 1100 पदों पर वैकेंसी निकाली है।

आईडीबीआई बैंक की ओर से जारी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो गई है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 19 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आईडीबीआई बैंक ने जोन के अनुसार जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के जिन 1100 पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें अहमदाबाद, चंढीगढ़ और चेन्नई के लिए 70-70; बेंगलुरु के 75, भोपाल, कोच्चि और पुणे में 55-55, भुवनेश्वर और नागपुर के 50-50, दिल्ली और मुंबई के 130-130, गुवाहाटी के 35, हैदराबाद के 65; कोलकाता के 60, लखनऊ के 85 और पटना के लिए 45 पद शामिल हैं।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ और निर्धारित अन्य योग्यता का होना आवश्यक है।

अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 मार्च के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो जनरल/ओबीसी/ईडब्लूएस उम्मीदवारों के लिए 1050 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए फीस निर्धारित की गई है।

आईडीबीआई बैंक की ओर से जारी पद के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वालों में से योग्य कैंडिडेट का चयन ऑनलाइन टेस्ट (ओटी), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी), पर्सनल इंटरव्यू (पीआई) और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट (पीआरएसटी) के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन 12 अप्रैल को सुबह की शिफ्ट में होने की संभावना है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें। निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद फॉर्म चेक कर सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

दुकान पर रिचार्ज कराते समय नंबर लीक होने का डर खत्म, बीएसएनएल लाया 'कवच नंबर'

नई दिल्ली, एजेंसी। महिलाओं को अक्सर अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक जगहों या रिटेल दुकानों पर रिचार्ज कराते समय शेयर करने में काफी हिचकिचाहट होती है। अपना पर्सनल नंबर अनजान लोगों को देने से प्राइवेसी लीक होने और अनचाहे कॉल्स का डर हमेशा सताता रहता है। महिलाओं की इसी बड़ी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (क्चस्हरु) ने एक बेहतरीन पहल की है। बीते 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर बीएसएनएल ने 'कवच नंबर' नाम से एक नई और सुरक्षित सर्विस लॉन्च की है, जो महिलाओं के पर्सनल नंबर को पूरी तरह से गुप्त रखने का दावा करती है।

कैसे काम करेगी क्चस्हरु की यह 'कवच नंबर' सुविधा?

बीएसएनएल की इस नई सर्विस का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की प्राइवेसी को और अधिक सुरक्षित और आसान बनाना है। इस सुविधा के तहत कंपनी महिलाओं को एसएमएस (स्नूस्) के जरिए 10 अंकों का एक अस्थाई (वैकल्पिक) नंबर मुहैया कराएगी। यह नया नंबर सीधे तौर पर उनके असली मोबाइल नंबर से लिंक होगा। अब जब भी कोई महिला किसी दुकान या रिटेल स्टोर पर अपना फोन रिचार्ज कराने जाएगी, तो उसे अपना असली नंबर दुकानदार को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। वह सिर्फ एसएमएस में मिला यह 'कवच नंबर' बताकर अपना फोन सुरक्षित तरीके से रिचार्ज करवा सकेंगी।

असली नंबर रहेगा पूरी तरह सेफ, ऐसे उठाएं लाभ

यह 'कवच नंबर' सच में महिलाओं की प्राइवेसी के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा। जो महिलाएं आज भी डिजिटल पेमेंट की जगह ऑफलाइन या रिटेल स्टोर पर जाकर रिचार्ज करवाना पसंद करती हैं, उनके लिए यह सर्विस बेहद काम की साबित होगी। बिना पर्सनल नंबर शेयर किए रिचार्ज भी हो जाएगा और नंबर पूरी तरह सेफ भी रहेगा। इस शानदार सुविधा का लाभ उठाने या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बीएसएनएल ग्राहक 'बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप' या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट की मदद ले सकती हैं।

यूनुस सरकार का किया भुगतेंगे तारिक रहमान, अमेरिका की ट्रेड डील से बांग्लादेश को होगा 1300 करोड़ टका का नुकसान

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार की जगह नई चुनी हुई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है, हालांकि उसे शुरुआती दिनों में ही भारी झटके लगने की संभावना नजर आ रही है। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के अनुसार, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के साथ साइन किए गए रेसिप्रोकल ट्रेड डील के तहत 6,700 से अधिक अमेरिकी उत्पादों को टैरिफ बेनिफिट देने से बांग्लादेश को हर साल इंपोर्ट टैक्स से होने वाली आय में करीब 1,327 करोड़ टका का नुकसान हो सकता है।

थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (CPD) ने कल मंगलवार को ढाका में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ (ART) पर राजकोषीय आय पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी दी, और नई सरकार से एक महीने पहले साइन किए गए एग्रीमेंट का रिव्यू करने की अपील की। CPD ने कहा, "बांग्लादेश को राजकोषीय बजट के नजरिए से एग्रीमेंट के असर का अच्छी तरह से आकलन करने और ART का रिव्यू करने के लिए अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने की जरूरत है।" CPD की ओर से यह ब्रीफिंग जुलाई में शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट पेश होने से पहले इससे जुड़े उपायों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। CPD ने चेतावनी दी कि इस एग्रीमेंट का बांग्लादेश के राजकोषीय और बजट से जुड़े फ्रेमवर्क पर बड़ा असर पड़ सकता है और यह देश की आर्थिक संप्रभुता पर भी सवाल उठा सकता है।

थिंक टैंक के मुताबिक, इस करार में तीसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं और यह सीमित करने की कोशिश की गई है कि सामान कहां से लिया जा सकता है और कहां से नहीं। इस दौरान CPD के फेलो मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को खत्म करने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बातचीत को लेकर एक नया रास्ता खोल दिया है।

बांग्लादेश में किस तरह का हुआ ट्रेड डील

एक सवाल के जवाब में रहमान ने कहा, "अगर बांग्लादेश चाहे, तो वह इस एग्रीमेंट को फिर से देख सकता है।" पिछले साल 2 अप्रैल को ट्रंप के नेशनल इमरजेंसी लॉ के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद बांग्लादेश को शुरू में 37 फीसदी प्रपोज्ड टैरिफ का सामना करना पड़ा था। बाद में रेट को घटाकर 35 फीसदी कर दिया गया, फिर बातचीत के दौरान 20 फीसदी कर दिया गया, और आखिर में पिछले महीने 12 फरवरी के आम चुनाव से 3 दिन पहले अंतरिम सरकार द्वारा साइन की गई डील के तहत 19 फीसदी कर दिया गया।

बांग्लादेश के इस करार को लेकर देश के कई प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट ने कड़ी आलोचना की। उनका तर्क था कि इसके कई प्रावधान अमेरिका के हितों के पक्ष में हैं और बांग्लादेश पर इसके लंबे समय तक असर पड़ सकता है। हालांकि करार के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपि ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 15 फीसदी का यूनिवर्सल टैरिफ लगा दिया। इस वजह से, बांग्लादेश पर अब 15 फीसदी का रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है। देश के मौजूदा एवरेज टैरिफ 16.15 फीसदी के साथ मिलाकर, बांग्लादेशी एक्सपोर्ट पर कुल टैरिफ का बोझ करीब 31.15 फीसदी बैठेगा। है। CPD की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश को करार के तहत तुरंत करीब 4,500 अमेरिकी उत्पादों को ड्यूटी-फ्री एक्सेस देना होगा, जबकि अगले 5 से 10 सालों में 2,210 और उत्पादों कैटेगरी को ड्यूटी-फ्री ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद है। इस तरह से CPD का कहना है कि अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी से वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 108.13 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,327 करोड़ टका (बांग्लादेशी मुद्रा) की कमाई हुई। इस तरह से देश को 1300 करोड़ से अधिक टके का नुकसान होने की उम्मीद है।

ईरान अभी भी बना सकता है 10 परमाणु बम...जंग के बीच IAEA चीफ की बड़ी चेतावनी

तेहरान, एजेंसी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था International Atomic Energy Agency (IAEA) के प्रमुख Rafael Grossi ने बड़ा खुलासा किया है कि ईरान अभी भी परमाणु बम बना सकता है। ग्रॉसी के मुताबिक, ईरान का बड़ा हिस्सा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान इलाके में जमीन के नीचे बनी एक सुरंग में रखा गया था और संभावना है कि यह सामग्री अब भी वहीं मौजूद हो सकती है। IAEA के अनुमान के अनुसार, पिछले साल युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। इस स्तर का यूरेनियम अगर और ज्यादा शुद्ध किया जाए तो उससे करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ग्रॉसी ने बताया कि इस्फहान में आखिरी निरीक्षण के समय करीब 200 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला यूरेनियम मौजूद था। पिछले साल अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। उस समय अमेरिका ने Northrop Grumman B-2 Spirit बमवर्षकों से भारी बंकर बस्टर बम गिराए थे, जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक तबाही मचाने में सक्षम हैं। हालांकि इस्फहान के पास मौजूद अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स इन हमलों में पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। IAEA प्रमुख ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य निगरानी तरीकों से अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इस्फहान से परमाणु सामग्री को कहीं और ले जाया गया हो। उनके मुताबिक, कुछ संवर्धित यूरेनियम नतांज केंद्र में भी मौजूद हो सकता है।

तालिबान से जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने 3 आतंकियों को बनाया शांतिदूत, कौन हैं?

काबुल। अफगानिस्तान से जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने 3 आतंकवादियों को शांतिदूत बनाकर काबुल भेजा है। इन तीनों ही आतंकियों का नाम है- फजलुर रहमान खलील, अब्दुल्ला शाह मजहर (पीर मजहर शाह) और कारी साजिद उस्मान। पाकिस्तान ने तीनों को ही तालिबान के नेता से बात करने के लिए भेजा है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि ये सभी धार्मिक नेता हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं दे सकते हैं।

बीबीसी ऊर्दू ने सूत्रों के हवाले से लिखा है- फजलुर, मजहर और उस्मान 2 दिन से काबुल में बैठे हैं। तीनों पहले पीओके में सक्रिय थे। इन तीनों को ही ऐसे वक्त में काबुल भेजा गया है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है।

फजलुर रहमान खलील- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्रिय रहा है। 1980 के दशक में हरकत-उल मुजाहिद्दीन का प्रमुख बनाया गया था। तालिबान के लड़ाकों के साथ खलील के अच्छे संबंध रहे हैं। खलील मूल रूप से खैबर पख्तूनख्वाह का रहने वाला है। तालिबान समर्थित टीटीपी इन्हीं इलाकों में कोहराम मचा रहा है। एक वक्त में फजलुर रहमान को कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड माना जाता था। वर्तमान में खलील पीओके के 2 मदरसों का प्रमुख है, जहां पर आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है। अब्दुल्ला शाह मजहर- काबुल में शांतिदूत बनकर गए अब्दुल्ला को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। अब्दुल्ला भी पीओके में आतंकी गतिविधियों को संचलित करता है। अब्दुल्ला वर्तमान में तहरीक-ए-गल्बा-ए-इस्लाम नामक एक पार्टी के प्रमुख पद पर काबिज है। अब्दुल्ला की पकड़ तालिबान के भीतर है। इसलिए उसे शांतिदूत बनाकर भेजा गया है। कारी साजिद उस्मान- कारी उस्मान अपने भाई साजिद की देखरेख में आतंकी बना। साजिद ने तालिबान के लिए सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद अभियान का नेतृत्व किया था। कारी उस्मान पाकिस्तान के साथ-साथ सऊदी और अफगानिस्तान में रहता है। पुराने रिश्तों का हवाला देकर उसे भी काबुल भेजा गया है। पाकिस्तान की सरकार चीन, कतर, सऊदी और तुर्की के सहयोग से तालिबान की सरकार से बात कर रही थी, लेकिन दोनों के बीच सीजफायर पर बात नहीं बन पा रही है। पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंजदा एक फतवा जारी करें, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों पर बैन की बात हो।

मिडिल ईस्ट में जंग से हाहाकार, होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो क्या होगा? कौन-से रास्ते बन सकते हैं विकल्प

तेल अवीव, एजेंसी। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजरें एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई हैं। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसे अमेरिका और ईरान में ठनी हुई है। दोनों देश इसे रास्ते को लेकर एक -दूसरे पर लगातार मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सबसे बड़ी लाइफलाइन माना जाता है। इस युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की काफी संभावना है, इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और कीमतों में भारी उछाल आ रहा है। हालांकि खाड़ी क्षेत्र के देशों ने

कुछ वैकल्पिक रास्ते और पाइपलाइन तैयार कर रखी हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है।

बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट

एक प्रमुख विकल्प बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट है। यह रास्ता लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यहां से जहाज स्वेज नहर के रास्ते यूरोप और भूमध्य सागर तक पहुंचते हैं। हालांकि यह मार्ग भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यमन में जारी संघर्ष और हूती विद्रोही के हमलों के कारण यहां भी जहाजों को खतरा बना रहता है।

सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन

होर्मुज स्ट्रेट का सबसे बड़ा वैकल्पिक इंतजाम सऊदी पूर्वपश्चिम पाइपलाइन है। इसे पेट्रोलाइन भी कहा जाता है। यह पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों से तेल को सीधे लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाती है। इससे तेल को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे बिना जहाजों में लोड किया जा सकता है। लेकिन इस पाइपलाइन की क्षमता इतनी नहीं है कि वह पूरी खाड़ी क्षेत्र की तेल सप्लाई को संभाल सके।

अबू धाबी से फुजैरा पाइपलाइन

संयुक्त अरब अमीरात ने भी हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन बनाई है। यह पाइपलाइन तेल को सीधे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंचाती है। फुजैरा ओमान की खाड़ी में स्थित है, इसलिए यहां से तेल भेजने के लिए जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती।

क्यों इतना अहम है होर्मुज स्ट्रेट

होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा चेकपॉइंट है। खाड़ी क्षेत्र के बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात अपना अधिकांश तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। अगर यह मार्ग लंबे समय के लिए बंद हो जाता है, तो दुनिया में तेल और गैस की भारी कमी हो सकती है, जिससे ऊर्जा संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है।

होर्मुज स्ट्रेट का कोई भी विकल्प पूरी तरह उसकी जगह नहीं ले सकता। पाइपलाइन और अन्य समुद्री मार्ग कुछ राहत जरूर दे सकते हैं, लेकिन वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए यह जलडमरूमध्य आज भी सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बना हुआ है।

पीएम मोदी की रैली से पहले गोयल का बड़ा दावा, तमिलनाडु में बदलाव के लिए एनडीए को चुनेगी जनता

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए का सीट बंटवारा समझौता सौहार्दपूर्ण तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनाव में एनडीए की जीत का विश्वास जताते हुए भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाएगा। आज तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इन चीजों (सीट बंटवारे) पर आपस में चर्चा करते हैं और जब हम इसे अंतिम रूप दे देंगे, तो हम प्रेस को सूचित करेंगे। इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा।

डीएमके की आलोचना करते हुए और तमिलनाडु में बदलाव का आह्वान करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा

कि एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी का विशाल जनसभा में स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित है। तमिलनाडु बदलाव और सुशासन चाहता है। वे स्टालिन सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें उदयनिधि स्टालिन की तमिल विरोधी संस्कृति और तमिल विरोधी नेतृत्व पसंद नहीं है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में तमिलनाडु में एनडीए के लिए समर्थन की लहर देखी जा सकती है। एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगा।

इसके अलावा, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर 'विभाजनकारी राजनीति' का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके उपमुख्यमंत्री और स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के लोगों से प्यार करते हैं, वे तमिल संस्कृति और गौरव का सम्मान करते हैं। वे चाहते हैं कि तमिलनाडु देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार की सभी नीतियां राज्य में लागू हों, साथ ही तमिलनाडु सरकार राज्य के लोगों के विकास के लिए काम करे... वह सरकार, जिसने TASMAC शराब घोटाला, रेत माफिया और कानून व्यवस्था की स्थिति को समाप्त किया है, अम्मा के सुनहरे दिनों की याद दिलाती है।

गोयल ने आगे कहा कि मतदाताओं के मतदान करने पर डीएमके के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। राज्य की जनता स्टालिन परिवार की विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करती। उनका परिवार विभाजित है और उन्होंने तमिलनाडु में राजनीति का स्तर बहुत गिरा दिया है। वे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन जनता का समर्थन खो चुके हैं। उनका परिवार उदयनिधि स्टालिन को स्वीकार नहीं करता। एमके स्टालिन डीएमके को उदयनिधि स्टालिन को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आधारशिला रखेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे।

पद संभालते ही तरनजीत संधू एक्टिव, दिल्ली के विकास पर गृह मंत्री अमित शाह से हुई पहली बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और लोक सेवा एवं शासन से संबंधित मामलों पर चर्चा की। X पर एक पोस्ट में तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। आपसी हित के मुद्दों और लोक सेवा एवं शासन से संबंधित मामलों पर सार्थक चर्चा हुई।

इससे पहले, संधू ने विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को विश्व की अन्य राजधानियों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। एएनआई से बात करते हुए तरनजीत संधू ने कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है, और हमें विश्व की सभी राजधानियों से प्रतिस्पर्धा और तुलना करनी होगी। हमें सबके साथ आगे बढ़ना होगा। हमारा ध्यान विकास पर है और होना चाहिए। दिल्ली के नए उपराज्यपाल (एलजी) नियुक्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रति आभार भी व्यक्त किया था।

संधू ने लिखा कि मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उनका नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन हमेशा से मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास और मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ। मैं दिल्ली और राष्ट्र की जनता की सेवा के लिए समर्पण, निष्ठा और विनम्रता के साथ प्रतिबद्ध हूँ।

तरनजीत संधू देश भर में राज्यपालों और उपराज्यपालों के व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा हैं। इस फेरबदल में, तरनजीत सिंह संधू ने वीके सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तरनजीत संधू 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार भी थे। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा का तबादला करके उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है।

आलिया भट्ट और शरवरी वाग की स्पाई थ्रिलर अल्फा की बदली रिलीज डेट, अब 10 जुलाई को थिएटर में दस्तक देगी फिल्म

आलिया भट्ट और शरवरी की आगामी फिल्म अल्फा की नई रिलीज डेट का आखिरकार आ ही गई। इससे इसके सिनेमाघरों में रिलीज होने को लेकर महीनों से चल रही अटकलों का अंत हो गया है। पिछले कुछ महीनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज को स्थगित किया जा सकता है। कुछ अफवाहों में यह भी कहा गया था कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी और सीधे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी। हालांकि मेकर्स के नए एलान से इसकी पुष्टि हो गई है कि फिल्म सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी।

आलिया भट्ट की लंबे समय से अटकी फिल्म अल्फा अब 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। यह फिल्म पहले दिसंबर 2025 और फिर अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट तय हो गई है।

मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें आलिया भट्ट की एक झलक दिखाई गई, साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में आधिकारिक जानकारी भी दी गई, जिसमें शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल शामिल हैं। अल्फा को पहले क्रिसमस 2025 को रिलीज करने की योजना थी। बाद में, मेकर्स ने तारीख बदलकर 17 अप्रैल, 2026 कर दी। हालांकि, उसी तारीख को सलमान खान अभिनीत फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी रिलीज होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस पर सीधे टकराव से बचने के लिए, फिल्म मेकर्स ने अल्फा को आगे की तारीख में रिलीज करने का फैसला किया।

अल्फा, यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स के पॉपुलर हिस्से का हिस्सा है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों में एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में शामिल हैं। हालांकि, अल्फा इस फ्रेंचाइजी की पहली फीमेल लीड वाली स्पाई थ्रिलर होगी, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी बड़े लेवल पर एक्शन सेट में हाई-ऑक्टेन स्टंट करेंगी।

'द 50' से बाहर होने के बाद निक्की तंबोली ने की क्रिप्टिक पोस्ट, निशाने पर कौन? बोलीं- फेक कमेंट करवाने...

इन दिनों रियलिटी 'द 50' में खूब हंगामा हो रहा है। कई प्रतियोगी शो से बाहर भी हो चुके हैं। इसी बीच 'द 50' से बाहर हो चुकीं प्रतियोगी और एक्ट्रेस निक्की तंबोली की क्रिप्टिक पोस्ट चर्चा में आ गई है।

निक्की तंबोली कुछ दिन पहले ही रियलिटी 'द 50' से बाहर हुईं। हाल ही में उनके बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल भी शो से बाहर हो गए। अब शो में कुछ इंफ्लुएंसर, टीवी आर्टिस्ट बाकी रह गए हैं। अपनी हालिया पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए निक्की तंबोली ने 'द 50' के कुछ प्रतियोगियों पर निशाना साधा है। जानिए, अपनी पोस्ट में निकी तंबोली ने क्या कहा? और कौन से प्रतियोगी पर वह निशाना साधा रही हैं।

अपनी पोस्ट में निकी तंबोली ने क्या लिखा?

निकी तंबोली ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है। इसमें वह लिखती हैं, 'मेरी पोस्ट पर फेक कमेंट्स करवाने से ज्यादा मेहनत अगर अपनी लाइफ पर करते तो शायद कोलेबोरेशंस से जिंदगी नहीं चलती। मेरी पोस्ट पर फेक कमेंट्स खरीदने से अच्छा है, अपनी रिस्पेक्ट खरीद लो। शायद ज्यादा काम आ जाए।' वह आगे लिखती हैं, 'गुस्सा जायज है। घाव गहरे थे।'

निक्की तंबोली के निशाने पर कौन था?

निक्की तंबोली ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि वह टीवी एक्टर प्रिंस नरुला और टीवी पर्सनालिटी शिव ठाकरे पर निशाना साध रही हैं। यह दोनों इस वक्त 'द 50' शो का हिस्सा हैं। जब निक्की और उनका बॉयफ्रेंड शो में थे तो शिव ठाकरे और प्रिंस नरुला से कई बार झगड़ा हुआ।

कौन बनेगा शो का विनर?

'द 50' शो में विनर बनने की दौड़ में शिव ठाकरे आगे दिख रहे हैं। इनके अलावा प्रिंस नरुला का नाम भी विनर के तौर पर सामने आ रहा है। दर्शक इन दोनों को काफी पसंद कर रहे हैं। 'द 50' शो की बात करें तो इसमें लगभग 50 प्रतियोगी शामिल हुए थे। जिसमें कुछ एक्टर, इंफ्लुएंसर, स्पोर्ट्स पर्सन थे। अब तक कई लोग शो से बाहर हो चुके हैं। यह रियलिटी शो जीयो हॉटस्टार पर और कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होता है।

लाहौर 1947 का बदला गया नाम? अब 13 अगस्त को 'बंटवारा 1947' टाइटल से रिलीज होगी सनी देओल की फिल्म

वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 से सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया। वहीं अब एक्टर आमिर खान प्रोडक्शन की फिलम से बड़े पर्दे पर फिस से धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अपकमिंग फिल्म का नाम पहले लाहौर 1947 रखा गया था। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म का टाइटल बदल दिया है। जानते हैं आमिर खान और सनी देओल स्टारर फिल्म का नया नाम क्या रखा जाएगा?

राजकुमार संतोषी निर्देशित मच अवेटेड फिल्म 'लाहौर 1947' का टाइटल बदला जा रहा है। दरअसल फिल्म मेकर्स को चिंता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के बीच लाहौर नाम जोड़ने से परेशानी हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'लाहौर 1947' का नाम बदलकर 'बटवारा 1947' कर दिया गया है। फिल्म का नाम बदलने का फैसला पिछले हफ्ते लिया गया था क्योंकि टीम सिफ़र् लाहौर पर फ़ोकस करने के बजाय 1947 के बंटवारे की दुखद घटना को दिखाने और एक बड़ी भावना दिखाना चाहती थी'

सनी देओल ने बताया कि लाहौर 1947 का आइडिया कैसे आया। बॉर्डर 2 स्टार ने बताया, यह एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर राजकुमार संतोषी और मैं सालों से बात कर रहे थे। हम इसे करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने आगे कहा, ज़ाहिर है, गदर के बाद यह मुमकिन हो गया। आमिर मेरे पास आए और कहा कि वह यह प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। बाद में, सबने हां कह दी।

फिल्म के बारे में बात करते हुए, सनी ने बताया था, सब्जेक्ट बहुत इमोशनल है। राजकुमार संतोषी और मैंने तीन इंटेंस फिल्में दी हैं। लाहौर 1947 में किरदारों में इंटेंसिटी और डेप्थ है। यह एक प्ले है जिसे अडैप्ट किया गया है। उम्मीद है, हम इसे जल्द से जल्द रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे।

असगर वजाहत के मशहूर प्ले जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्याई नी पर बेस्ड यह फिल्म पार्टीशन के समय की है। कहानी एक मुस्लिम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो लखनऊ से लाहौर माइग्रेट करता है और उसे एक हिंदू परिवार द्वारा खाली की गई हवेली अलॉट की जाती है। हालांकि, चीजें तब ड्रामैटिक मोड़ लेती हैं जब उन्हें पता चलता है कि हिंदू परिवार अभी भी घर में रह रहा है और जाने से मना कर रहा है।

बता दें कि आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म भारत के 1947 के बंटवारे के समय की है और इसमें आमिर के साथ सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह हैं। यह असगर वजाहत के नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई एन' पर आधारित है। ये फिल्म इस साल 13 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com